मुंबई (महाराष्ट्र) से प्रकाशित
हिन्दी दैनिक
उत्तरशक्ति
हर खबर निष्पक्षता के साथ
मुंबई
वर्षः 9 अंक 04
गुरुवार, 9 जुलाई 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

देशभर में मानसून का कहरः गुजरात-महाराष्ट्र में बारिश से त्राहि-त्राहि, कई राज्यों में अलर्ट

नई दिल्ली/ मुंबई, 8 जूलाई। देश के कई हिस्सों में बुधवार को भारी मानसूनी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश के कारण बाढ़, जलभराव, भूस्खलन और यातायात बाधित होने की घटनाएं सामने आईं। गुजरात के सूरत शहर में पिछले 24 घंटों में 358 मिमी बारिश हुई, जिससे कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए और जगह-जगह पानी भरने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी बारिश से प्रभावित राज्यों की स्थिति की जानकारी लेने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

पीटीआई के अनुसार, सूरत के निचले इलाकों से 3,400 से ज्यादा लोगों को बचाया गया और 3,800

से ज्यादा लोगों को दूसरी जगहों पर भेजा गया। कई जगहों पर घरों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दुकानों में भी पानी घुस गया। पानी भरने की वजह से सिटी बस सेवा समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी प्रभावित हुआ। वराछा इलाके में पोद्दार आर्केड की ग्राउंड-फ्लोर की दुकानें पूरी तरह पानी में डूबी हुई थीं। सूरत के कलेक्टर तेजस परमार ने बताया कि खाड़ी (क्रीक) के पास के इलाकों, जैसे लिंबायत, उधना, वराछा और कड़ोदरा में जलभराव की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि शहर के जलभराव वाले इलाकों में बनी ऊंची इमारतों में भी खाने के पैकेट बांटे गए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में कैबिनेट की बैठक में राज्य भर में बारिश की स्थिति की समीक्षा की और मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे बारिश से प्रभावित जिलों का दौरा करें। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में कचरे का बड़ा ढेर गिरने से एक तीन मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें 16 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। राज्य में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई स्थानों पर जलभराव तथा भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है।

मुंबई में भारी बारिश के कारण लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं और कई इलाकों में पानी भर गया। पालघर के वसई-विरार क्षेत्र में जलभराव के कारण गुजरात की ओर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें भी प्रभावित हुईं। आईएएनएस के अनुसार, एक जून को मानसून सीजन शुरू होने के बाद से राज्य में 62 लोगों की मौत हुई है और 200 जानवरों की जान गई है। पालघर में एक गांव में स्थानीय लोगों ने घर के दरवाजे को स्ट्रेचर बनाकर गहरे पानी से गुजरते हुए गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया।

केरल के वायनाड में सुरंग सड़क निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन के बाद पांच लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। हादसे में अब तक तीन श्रमिकों की मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मामले में अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एनडीआरएफ, दमकल कर्मी और खोजी कुत्तों की मदद से अभियान चलाया जा रहा है। लगातार बारिश राहत कार्य में बाधा बन रही है। एएनआई के अनुसार, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है और उत्तर-पश्चिम, मध्य, पश्चिमी तट तथा पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने बंगाल के उप-हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक तट, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और केरल में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश, गरज-चमक और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है।

सरकार ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए कदम, अमित शाह ने ATRS लागू करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली, 8, जुलाई। देश में हवाई यात्रा करने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने यांत्रिक सुविधाओं को बेहतर करने के लिए त्वरित तरीके से काम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु के साथ प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था एवं आप्रवासन प्रणाली की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव, सीआइएसएफ महानिदेशक और एएआइ अध्यक्ष सहित दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री ने सभी हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से ऑटोमैटिक ट्रे रिट्राइवल सिस्टम (एटीआरएस) लागू करने का निर्देश दिया। नए हवाई अड्डों में इस सिस्टम को अनिवार्य रूप से स्थापित करने के मापदंड तय किए जाएंगे। इससे मानव संसाधन लागत में काफी कमी आएगी। यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट के हर टच-प्वाइंट (एंट्री लेन, चेक-इन काउंटर, सुरक्षा जांच और आप्रवासन काउंटर) के बीच समन्वित योजना तैयार की गई है। इसमें यात्रियों के आवागमन में किसी भी प्रकार का अवरोध न हो, इसका ध्यान रखा गया है। सरकार की योजना 21 निमार्णाधीन और 41 अन्य हवाई अड्डों सहित कुल 62 हवाई अड्डों को अगले दो वर्षों में नया रूप देते हुए विकसित करने की है। विकास की प्राथमिकता यात्रियों की आवाजाही के आधार पर तय होगी। यात्री सुविधाएं बीसीएएस सुरक्षा मापदंडों के अनुसार बढ़ाई जाएंगी। सभी हवाई अड्डों के लिए एरोब्रिज की संख्या निर्धारित करने के मानदंड तैयार किए जाएंगे। बैगेज ड्रॉप सुविधा प्रमुख 16 हवाई अड्डों के अलावा अन्य उच्च ट्रैफिक वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। एक्स-रे स्क्रीनिंग के लिए सीआइएसएफ स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता भी सुनिश्चित करने का फैसला किया गया है। उपयुक्त योग्यता वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को ही इस कार्य में लगाया जाएगा।

यूपी में नए लेबर कोड लागू करने की तैयारी पूरी, जल्द मिल सकती है कैबिनेट से मंजूरी

लखनऊ, 8 जुलाई । प्रदेश में चार नई श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी श्रम संहिताओं के अनुरूप राज्य सरकार ने नियमावली का मसौदा तैयार कर उस पर मिली आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण कर लिया है। एक दो सप्ताह में राज्य नियमावली को अंतिम रूप देकर जल्द ही कैबिनेट की स्वीकृति के लिए रखा जा सकता है। नई व्यवस्था में जटिल श्रम कानूनों की जगह चार श्रम संहिताएं लागू होंगी। इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना, सभी श्रमिकों को न्यूनतम सुरक्षा देना, डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था लागू करना तथा गिग, प्लेटफार्म और निश्चित अवधि (एफटीई) जैसे नए रोजगार स्वरूपों को कानूनी मान्यता देना है। वेतन संहिता, 2019 के तहत सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित होगा। समान कार्य के लिए पुरुष और महिला को समान वेतन मिलेगा, ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से होगा और कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत मूल वेतन माना जाएगा। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में एफटीई कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसे अधिकार, एक वर्ष की सेवा पर ग्रेच्युटी, 300 तक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों के लिए छंटनी नियमों में बदलाव, हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस और त्वरित श्रम न्यायाधिकरण की व्यवस्था होगी।सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पहली बार गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगी। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 के तहत आनलाइन पंजीकरण, सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र, महिलाओं को सुरक्षा और सहमति के साथ सभी शिफ्टों में काम की अनुमति, 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच तथा प्रतिदिन आठ घंटे और सप्ताह में 48 घंटे कार्य का प्रविधान होगा। दुर्घटना या मृत्यु के मामलों में लगाए गए जुमार्ने का कम से कम 50 प्रतिशत पीड़ित को दिया जाएगा।

वर्क फ्रॉम होम, स्कूल बंद, पुणे की कई ट्रेनें कैंसल, एयरलाइंस की अडवाइजरी, मुंबई बारिश के बड़े अपडेट्स

मुंबई, 8 जुलाई। लगातार हो रही भारी बारिश से मुंबई में जनजीवन प्रभावित हो गया है। कर्जत-लोनावला के बीच भोर घाट सेक्शन में भूस्खलन होने के कारण मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इस संबंध में सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) स्वप्निल नीला ने जानकारी दी। स्वप्निल नीला ने बताया कि लगातार बारिश के कारण कर्जत-खोपोली रेल मार्ग प्रभावित हुआ है। पिछले तीन दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते कर्जत-लोनावला के बीच भोर घाट सेक्शन में भूस्खलन हुआ है। इसकी सूचना सभी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग के तीनों रेल ट्रैक प्रभावित हुए हैं। सीपीआरओ के अनुसार, भूस्खलन की घटना में किसी ट्रेन या यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मुंबई से पुणे जाने वाली लगभग 16 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 9 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित (डायवर्ट) किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें और सफर से पहले रेलवे द्वारा जारी ताजा अपडेट अवश्य देख लें। मुंबई सेंट्रल रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि ट्रेन नंबर 69174 दहानू रोडझबोरीवली को विरार में ही रोक दिया गया है (शॉर्ट-टर्मिनेट) और यह विरार और बोरीवली के बीच रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 69139 बोरीवलीझवलसाड मेमो बोरीवली के बजाय विरार से चलेगी और यह बोरीवली और विरार के बीच रद्द रहेगी। मुंबई सेंट्रल से वापी ट्रेन नंबर 59045 और वापी से मुंबई सेंट्रल ट्रेन नंबर 59040 रद्द कर दी गई है।

आर्केस्ट्रा के नाम पर अश्लील डांस पर लगेगी रोक, महाराष्ट्र विधान परिषद में भी पास हुआ संशोधन विधेयक

मुंबई, 8 जूलाई। विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी महाराष्ट्र के होटल, रेस्टोरेंट और बार में चल रहे आर्केस्ट्रा और लाइव म्यूजिक के नाम पर होने वाली अश्लीलता पर लगाम कसने के लिए डांस इन होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड बार रूम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वूमेन एक्ट, 2016 में संशोधन के लिए विधेयक को पास कर दिया गया। अब इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा वहां से मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट और बार रूम में आयोजित की जाने वाली लाइव संगीत (आर्केस्ट्रा) कार्यक्रम में डांस करने वाली डांसरो के साथ अश्लीलता करने और उन्हें छूने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर द्वारा पेश किया गया यह विधेयक का उद्देश्य महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना और मनोरंजन के नाम पर संचालित होने वाले अवैध और अश्लील कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है। गृह राज्य मंत्री भोयर ने कहा कि इससे पहले जो व्यवस्था थी उसके तहत होटलों और रेस्टोरेंट्स में लाइव म्यूजिक या आर्केस्ट्रा चलाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत अनुमति ली जाती थी। लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों से यह बात सामने आई कि पुलिस अधिनियम के तहत मिलने वाले लाइसेंस का इस्तेमाल कई जगहों पर सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया था। नए संशोधन के बाद अब यह लाइसेंस सीधे वर्ष 2016 में बने उस विशेष कानून के अंतर्गत दिए जाएंगे।इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लाइसेंस देने और उसकी निगरानी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही सीधे तय हो सकेगी। किसी भी तरह की शिकायत पर पुलिस अधिनियम की जगह इस विशेष कानून की धाराओं का इस्तेमाल करके तेजी से कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार ने साफ तौर पर तय कर दिया है कि जो भी प्रतिष्ठान अश्लीलता फैलाने के खिलाफ बनाए गए नियमों को तोड़ेगा, उसे तीन मौके दिए जाएंगे। पहला उल्लंघन इसमें प्रतिष्ठान को भारी जुमार्ना लगाया जा सकता है और नोटिस जारी किया जाएगा।

पाकिस्तान में 4 दिनों में 38 जवान ढेर, विद्रोहियों के हमलों से कांपा बलूचिस्तान, ISPR ने भारत पर मढ़ा दोष

इस्लामाबाद, 8 जुलाई। पाकिस्तान की सेना ने बुधवार को बताया कि पिछले चार दिनों में बलूचिस्तान में विद्रोहियों के तीन बड़े हमलों में 38 सुरक्षाकर्मी और चार आम नागरिक मारे गए हैं। इसे हाल के महीनों में पाकिस्तान में हुई हिंसा की सबसे घातक घटनाओं में से एक माना जा रहा है। ये सुरक्षाकर्मी विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैनात किए गए थे। इस दौरान 54 से ज्यादा विद्रोहियों को मार गिराने का भी दावा किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने इन हमलों को लेकर बिना किसी सबूत दिए भारत पर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान पर भी इन विद्रोहियों को शरण देने का आरोप लगाया है। बलूचिस्तान में हुए इन हमलों को सुरक्षा व्यवस्था की नाकामियों से जोड़कर देखा जा रहा है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, जिसकी सीमा अफगानिस्तान और

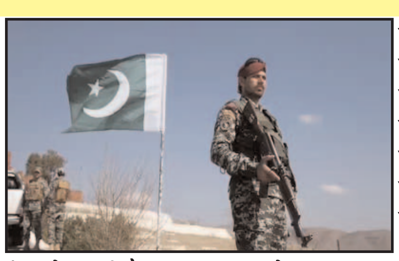

ईरान से लगती है। बलूचिस्तान लंबे समय से बलूच लिबरेशन आर्मी के नेतृत्व में विद्रोह का सामना कर रहा है। वहीं, पाकिस्तान तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) भी इस इलाके में पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने आरोप लगाया है कि बलूचिस्तान में जारी हिंसा और हमलों के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है। उसने तालिबान पर टीटीपी समेत दूसरे हथियारबंद समूहों को शरण देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत पर भी इन समूहों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। भारत और अफगान तालिबान ने हर बार पाकिस्तान के इन आरोपों को खारिज किया है। तालिबान ने तो इसे पाकिस्तान के अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्थाओं की नाकामी बताया है।

बुधवार को मीडिया को जानकारी देते हुए सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने इन तीन हमलों से जुड़े ऑपरेशन में 54 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में लड़ाई जारी है। चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो जिन तीन बड़े ऑपरेशन के बारे में मैंने आपको बताया, उनमें पहले चार आम नागरिक और बाद में हमारे पुलिस और सेना के जवान शहीद हुए, कुल मिलाकर 42 लोग शहीद हुए हैं।

सेना के अनुसार, पहला हमला 4 और 5 जुलाई को क्वेटा के पास हन्ना उराक घाटी में हुआ, जहां TTP लड़ाकों ने स्थानीय ग्रामीणों पर हमला किया, जिसमें चार आम नागरिक मारे गए और छह अन्य घायल हो गए। दूसरा हमला 6 जुलाई को हुआ जब ळ्ळढ के आतंकवादियों ने जियारत जिले में मांगी बांध की सुरक्षा कर रही पुलिस चौकी पर हमला किया। चौधरी ने बताया कि शुरूआती हमले में नौ पुलिस अधिकारी मारे गए, जबकि सुरक्षा बलों ने 15 आतंकवादियों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने लगभग 18 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया और सुरक्षा बलों के उन तक पहुंचने से पहले ही उनकी हत्या कर दी। बाद में लड़ाई जारी रहने के दौरान 11 और आतंकवादी मारे गए।

नवी मुंबई में तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर, 10 पैदल चलने वालों को टक्कर मारी

मुंबई, 8 जुलाई। नवी मुंबई में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। नवी मुंबई में एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार के ड्राइवर ने कथित तौर पर गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और एक बड़ा 'हिट-एंड-रन' हादसा कर दिया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 12 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर घटना स्थल से गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि यह हादसा तलोजा फेज 1 इलाके में हुआ। शुरूआती जानकारी के मुताबिक, इलेक्ट्रिक कार ने सबसे पहले सड़क पर चार-पांच गाड़ियों को टक्कर मारी, जिससे काफी नुकसान हुआ। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 12 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर क्षतिग्रस्त गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। हादसे की असल वजह और घटनाक्रम की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें हादसे की गंभीरता और उसके बाद की स्थिति देखी जा सकती है। इस हादसे से इलाके के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया। जहां घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है और पुलिस की ओर से आगे की जांच जारी है।

हिंद-प्रशांत में भारत का बढ़ता सामर्थ्य एवं साझेदारियां

-ललित गर्ग

भारत आज केवल विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति ही नहीं, बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने जिस आत्मविश्वास, स्पष्टता और दूरदृष्टि का परिचय दिया है, उसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल दी है। कभी जो भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशी हथियारों पर निर्भर था, वही भारत आज आधुनिक मिसाइलों, रक्षा प्रणालियों और सैन्य उपकरणों का निर्यात करने वाला विश्वसनीय राष्ट्र बन चुका है। यह परिवर्तन केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक, वैज्ञानिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति का भी प्रमाण है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया सहित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ हुई उच्चस्तरीय वाताएं इस नई विदेश नीति की सफलता का सशक्त उदाहरण हैं। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, तकनीक और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्रों में हुए समझौते यह स्पष्ट करते हैं कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है।

भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है। वर्षों तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक माना जाता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल, आकाश वायु रक्षा प्रणाली, पिनाका रॉकेट सिस्टम, तेजस लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक रक्षा उपकरण आज विश्व के अनेक देशों का विश्वास जीत रहे हैं। भारत की स्वदेशी अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल आज केवल भारतीय सेना की शक्ति का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि विश्व के अनेक देशों की सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम भी बन रही हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकवाद विरोधी अभियानों में इन हथियारों की प्रभावशीलता ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। यही कारण है कि इंडोनेशिया जैसे महत्वपूर्ण देश अपने सुखोई लड़ाकू विमानों के लिए अस्त्र मिसाइल प्राप्त करना चाहते हैं तथा ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह भारत के रक्षा उद्योग के प्रति बढ़ते वैश्विक विश्वास का प्रमाण है।

इंडोनेशिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। मलक्का जलडमरूमध्य जैसे विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग पर उसकी रणनीतिक स्थिति वैश्विक व्यापार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग केवल दो देशों के संबंधों को मजबूत नहीं करता, बल्कि पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी नया आयाम देता है। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा और संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से दोनों देशों का सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत अब किसी पर निर्भर होकर नहीं, बल्कि समान साझेदारी और परस्पर सम्मान के आधार पर संबंध स्थापित कर रहा है। भारत किसी देश पर अपनी शक्ति थोपने में विश्वास नहीं रखता। उसकी विदेश नीति का मूल मंत्र है-वसुधैव कुटुम्बकम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और विश्व बंधुत्व। यही कारण है कि भारत जहां अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है, वहीं दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ भी विश्वासपूर्ण साझेदारी विकसित कर रहा है।

आज हिंद-प्रशांत क्षेत्र विश्व राजनीति का केंद्र बन चुका है। चीन का विस्तारवादी रवैया, दक्षिण चीन सागर में उसका सैन्यीकरण, छोटे देशों पर दबाव बनाने की नीति तथा आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास विश्व समुदाय के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। भारत ने इन परिस्थितियों में संतुलित, शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ रणनीति अपनाई है। भारत किसी के विरुद्ध युद्ध नहीं चाहता, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से कोई समझौता भी नहीं करता। यही संतुलित दृष्टिकोण भारत को विश्व का विश्वसनीय साझेदार बनाता है। भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए स्पष्ट संदेश है कि नया भारत अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। भारत अब केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आधुनिक तकनीकी युद्ध की तैयारियों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन इस दिशा में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है।

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं की सबसे बड़ी सफलता यह रही है कि उन्होंने भारत की वैश्विक छवि को अभूतपूर्व ऊंचाई प्रदान की है। आज विश्व के बड़े राष्ट्र भारत को केवल विशाल बाजार के रूप में नहीं, बल्कि विश्वसनीय मित्र, तकनीकी साझेदार, निवेश गंतव्य और सुरक्षा सहयोगी के रूप में देख रहे हैं। जी-20 की सफल अध्यक्षता, क्वाड की सक्रिय भूमिका, इंडो-पैसिफिक सहयोग, वैश्विक दक्षिण की आवाज तथा जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भारत का नेतृत्व इसकी पुष्टि करता है। भारत की विदेश नीति अब केवल कूटनीतिक दस्तावेज नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय विकास का सशक्त माध्यम बन चुकी है। रक्षा निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है, लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, अनुसंधान एवं नवाचार को नई गति मिल रही है और भारतीय उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत हो रहे हैं। यह विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र सदैव शांति, सह-अस्तित्व और परस्पर सम्मान रहा है। आदर्श स्थिति में किसी भी दो देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की नींव किसी तीसरे देश के प्रति वैमनस्य या शत्रुता पर नहीं, बल्कि साझा विकास, सुरक्षा और स्थिरता पर आधारित होनी चाहिए। किंतु अंतरराष्ट्रीय राजनीति आदर्शों से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों और शक्ति-संतुलन से संचालित होती है। आज चीन और पाकिस्तान अपने सैन्य एवं आर्थिक गठजोड़ को सऊदी अरब तक विस्तार देने के प्रयासों में जुटे हैं। हाल के सप्ताहों में सऊदी नेतृत्व और बीजिंग के बीच बढ़ती सक्रियता इस बदलते भू-राजनीतिक समीकरण का संकेत है। यद्यपि सऊदी अरब की प्राथमिक सुरक्षा चिंताएं पाकिस्तान और चीन से अलग हैं तथा उसका प्रमुख ध्यान खाड़ी क्षेत्र में ईरान के बढ़ते प्रभाव पर केंद्रित है, फिर भी बदलते वैश्विक समीकरण भारत के लिए सतर्क रहने का संदेश देते हैं। पाकिस्तान हर परिस्थिति में भारत के विरुद्ध रणनीतिक लाभ उठाने का अवसर तलाशता है, जबकि चीन अपने विस्तारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करने का प्रयास करता है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी, संतुलित और सक्रिय विदेश नीति भारत के हितों की प्रभावी सुरक्षा करती दिखाई देती है। उनकी कूटनीति केवल मित्र देशों के साथ विश्वास बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन और पाकिस्तान की शरारतों, षड्यंत्रों तथा सामरिक चुनौतियों का संयमित और दृढ़ता से सामना करने की क्षमता भी प्रदर्शित करती है। यही दूरगामी सोच भारत को एक विश्वसनीय, जिम्मेदार और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। आज विश्व एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो शक्ति और शांति, विकास और सुरक्षा, तकनीक और मानवता के बीच संतुलन स्थापित कर सके। भारत इस भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह सिद्ध किया है कि सशक्त राष्ट्र वही होता है जो अपनी रक्षा करने में सक्षम होने के साथ-साथ विश्व शांति और मानव कल्याण का भी वाहक बने। निस्संदेह भारत अब विस्तारवाद का नहीं, विकासवाद का प्रतीक है। वह हथियारों का निर्माण युद्ध भड़काने के लिए नहीं, बल्कि शांति की रक्षा और संतुलन स्थापित करने के लिए कर रहा है। यही भारत की सांस्कृतिक चेतना, लोकतांत्रिक मूल्यों और जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्व की पहचान है। आने वाले वर्षों में भारत की यही संतुलित विदेश नीति, आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति और विश्वसनीय कूटनीतिक नेतृत्व न केवल विकसित भारत के स्वप्न को साकार करेगा, बल्कि विश्व व्यवस्था को भी अधिक सुरक्षित, संतुलित और न्यायपूर्ण दिशा प्रदान करेगा।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता का इथेनॉल पथः उम्मीदों की उड़ान और व्यावहारिक अवरोध

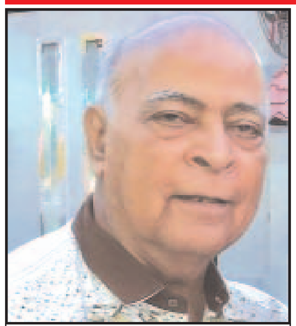

अशोक भाटिया

इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जुझारूपन ने फरवरी से दुनिया को ऊर्जा संकट में डाल दिया है, और मोदी सरकार की कारों में पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाने की आवश्यकता का कुछ लोगों द्वारा उपहास किया गया है क्योंकि 'दूध में पानी की मात्रा बढ़ाने से दूध की मांग कम हो जाएगी'। लेकिन सरकार की इस सोच में कुछ भी गलत नहीं है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल के इस्तेमाल को कम करने के प्रयोग पूरी दुनिया में चल रहे हैं, इसलिए यह सही है कि भारत में इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, जो तेल आयात पर निर्भर है ।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और आर्थिक प्राथमिकताओं के एक अभूतपूर्व चौराहे पर खड़ा है ऐसे समय देश ने हाल ही में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण (E20) का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले ही हासिल कर दुनिया के सामने नीतिगत इच्छाशक्ति का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। वर्ष 2013-14 में जहां इथेनॉल मिश्रण की दर महज 1.5 प्रतिशत के आसपास सिमटी हुई थी, वहीं 2025-26 के कालखंड में इसका देशव्यापी स्तर पर 20 प्रतिशत तक पहुंच जाना भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की एक युगांतकारी घटना है? इस नीतिगत उछाल का प्राथमिक श्रेय केंद्र की मोदी सरकार के 'इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम' को जाता है, जिसने भारत को जीवाश्म ईंधनों की विदेशी निर्भरता से मुक्त कराने और 'पंचामृत' के तहत वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का संकल्प लिया है।

परंतु, इस बड़ी नीतिगत सफलता के साथ ही धरातल पर कुछ ऐसे बुनियादी सवाल और व्यावहारिक चुनौतियां भी सिर उठाने लगी हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना इस दीर्घकालिक अभियान को कमजोर कर सकता है। हाल ही में राष्ट्रव्यापी स्तर पर E20 ईंधन के अनिवार्य प्रसार के बाद से आम उपभोक्ताओं, मोटर वाहन उद्योग और कृषि-अर्थशास्त्रियों के बीच एक त्रिपक्षीय बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मुद्रा की बचत का अचूक हथियार मानती है, वहीं दूसरी तरफ आम नागरिक माइलेज में गिरावट और पुराने वाहनों के इंजनों की सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। ऐसे में यह नीतिगत समीक्षा का सही समय है कि क्या भारत अपनी हरित ऊर्जा की रफ्तार को बनाए रखते हुए आम जनता की चिंताओं को वैज्ञानिक और आर्थिक धरातल पर संतुष्ट कर पा रहा है? इस नीति की आवश्यकता को समझने के लिए सबसे पहले भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता के आंकड़ों को देखना होगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लगभग 88.5 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। वैश्विक राजनीति में होने वाले उतार-चढ़ाव, खाड़ी देशों के तनाव और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भारत के घरेलू बाजार और बजटीय संतुलन को सीधे प्रभावित करती है। सरकार की इस इथेनॉल नीति ने देश की मैक्रो-इकोनॉमी को एक बड़ा सुरक्षा कवच दिया है। 2014-15 से लेकर मई 2026 तक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस कार्यक्रम के माध्यम से देश ने 1.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत की है और करोड़ों मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात को घरेलू जैव-ईंधन से प्रतिस्थापित किया है।

इस आर्थिक चक्र का दूसरा सबसे खूबसूरत पहलू इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ाव है। जैव-ईंधन का उत्पादन केवल फैक्टरियों की चहारदीवारी में नहीं, बल्कि देश के अन्नदाताओं के खेतों से शुरू होता है। गन्ने के उप-उत्पाद (शीरा), मक्का, और टूटे हुए चावल (सरप्लस अनाज) से इथेनॉल बनाने की अनुमति देकर सरकार ने किसानों को केवल 'अन्नदाता' से 'ऊर्जादाता' के रूप में परिवर्तित करने का सफल प्रयास किया है। इस खरीद प्रक्रिया के माध्यम से किसानों और घरेलू डिस्टिलरीज को लगभग 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सीधा भुगतान हुआ है, जिससे ग्रामीण अंचलों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं और चीनी मिलों के गन्ना बकाया संकट पर काफी हद तक लगाम लगी है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो E20 मिश्रण ने देश के वायुमंडल को लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से बचाया है, जो महानगरों में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ी राहत है।

नीतिगत स्तर पर जितनी यह योजना आकर्षक और देशहित में दिखाई देती है, उपभोक्ता स्तर पर इसके अनुभव उतने ही मिश्रित रहे हैं। देश के करोड़ों दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों द्वारा लगातार यह शिकायत की जा रही है कि E20 पेट्रोल के उपयोग के बाद से वाहनों के माइलेज में 6 से 7 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बात सही भी है; इथेनॉल का ऊर्जा घनत्व शुद्ध पेट्रोल की तुलना में लगभग एक तिहाई कम होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि समान दूरी तय करने के लिए इंजन को अधिक ईंधन की खपत करनी पड़ती है। आज के इस महंगाई के दौर में, जब पेट्रोल की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं, आम नागरिक को कम माइलेज के रूप में अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ महसूस हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, तकनीकी मोर्चे पर सबसे बड़ी चिंता 'मटेरियल डिग्रेडेशन' यानी वाहनों के पुर्जों के खराब होने की है। इथेनॉल स्वभाव से 'हाइग्रोस्कोपिक' होता है, जिसका मतलब है कि यह हवा से नमी और पानी को बहुत तेजी से सोखता है। यह रासायनिक गुण पुराने वाहनों (जो विशेष रूप से E20 के अनुकूल नहीं बने हैं) के ईंधन टैंक, पाइपलाइन और कार्बोरेटर या इंजेक्टर प्रणालियों में जंग और प्लास्टिक या रबर के पुर्जों के गलने का कारण बन सकता है। यद्यपि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और प्रमुख वाहन निर्माताओं जैसे मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प ने सेवा डेटा का हवाला देते हुए दावा किया है कि E20 से पुराने इंजनों को कोई बड़ा या गंभीर नुकसान नहीं देखा गया है, फिर भी आम जनता के भीतर बैठा अविश्वास और डर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

जनता के इसी जमीनी विरोध और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र की अपूर्ण तैयारी को देखते हुए मोदी सरकार ने हाल ही में बेहद परिपक्वता और वैज्ञानिक संयम का परिचय दिया है। पहले बाजार में ऐसी अटकलें जोरों पर थीं कि सरकार E20 की तत्काल सफलता के बाद तेजी से 25 प्रतिशत सम्मिश्रण (E25) की ओर बढ़ेगी। परंतु, उपभोक्ताओं के फीडबैक और वाहनों की तकनीकी सीमाओं को स्वीकार करते हुए पेट्रोलियम और परिवहन मंत्रालयों ने स्पष्ट कर दिया है कि E25 को लागू करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं की जाएगी। सरकार ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि वर्तमान में E20 ईंधन पूरी तरह से सुरक्षित है और उच्च मिश्रणों की तरफ कदम केवल व्यापक वैज्ञानिक परीक्षणों, ऑटोमोबाइल उद्योग की तैयारियों और उपभोक्ताओं की सहमति के बाद ही बढ़ाया जाएगा।

सरकार की इस 'ग्रेडेड अप्रोच' की सराहना की जानी चाहिए। किसी भी देशव्यापी नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह देश के अंतिम नागरिक के हितों के साथ कितनी सहजता से मेल खाती है। यदि सरकार बिना पर्याप्त बुनियादी ढांचे के जबरन उच्च मिश्रण थोपती, तो इससे न केवल वाहन बाजार में व्यवधान उत्पन्न होता, बल्कि हरित ऊर्जा कार्यक्रमों के प्रति जनता में एक स्थायी आक्रोश और अविश्वास पैदा हो सकता था। इस लेख में एक और गहरे आर्थिक और सामाजिक संकट की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है, जो नीति निमार्ताओं के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वह है–'अन्न बनाम ईंधन' का द्वंद्व। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में खाद्य सुरक्षा हमेशा से सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। जब हम इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के जूस, मक्का और विशेष रूप से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से मिलने वाले चावल का अत्यधिक उपयोग करने लगते हैं, तो इसका सीधा असर देश के खाद्य बाजार पर पड़ता है। विगत वर्षों में चीनी के घरेलू दामों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार को कई बार इथेनॉल उत्पादन पर अस्थायी प्रतिबंध या सीमाएं लगानी पड़ी थीं, हालांकि बाद में आपूर्ति सामान्य होने पर इन प्रतिबंधों को हटा लिया गया। यदि किसान अनाज उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा केवल ऊर्जा क्षेत्र की व्यावसायिक डिस्टिलरीज को बेचने लगेंगे, तो देश में पशुओं के चारे (जैसे मक्के से बनने वाले फीड) और आम जनता के उपभोग वाले खाद्यान्न की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो सकती है। इसलिए, नीति की निरंतरता के लिए कृषि भूमि के उपयोग और फसलों के चक्र का सटीक वैज्ञानिक मानचित्रण अनिवार्य है।

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम भारत के उज्ज्वल और स्वच्छ भविष्य के लिए एक गैर-परक्राम्य आवश्यकता है, लेकिन इसकी सफलता का रास्ता आम जनता की जेब और भरोसे से होकर ही गुजरता है। इस नीति को बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तीन रणनीतिक कदमों पर विचार किया जाना चाहिएः

उपभोक्ताओं को कम माइलेज के दर्द से राहत देने का सबसे तार्किक तरीका 'मूल्य प्रोत्साहन' है। सरकार को ए20 या भविष्य के उच्च इथेनॉल मिश्रित ईंधनों की कीमत शुद्ध पेट्रोल या 'ॉ८ फ्यूल की तुलना में 5 से 7 प्रतिशत कम रखनी चाहिए। जब उपभोक्ता को ईंधन की कीमत में सीधी छूट मिलेगी, तो माइलेज की मामूली कमी की भरपाई आर्थिक रूप से हो जाएगी, और वे स्वेच्छा से पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का चयन करेंगे।

जरुरत है सरकार और तेल विपणन कंपनियों को केवल दावों के बजाय प्रयोगशालाओं के प्रामाणिक डेटा को जनता के सामने रखना चाहिए। पुराने वाहनों की देखभाल कैसे करें, इथेनॉल ईंधन के उपयोग के दौरान किन सावधानियों को बरतें, इसके बारे में पेट्रोल पंपों पर ही बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।तथा खाद्यान्न और गन्ने पर निर्भरता कम करने के लिए पराली, बांस, और कबाड़ से बनने वाले 'सेकंड जनरेशन' (2G) इथेनॉल के बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करना होगा।

, भारत का इथेनॉल कार्यक्रम ऊर्जा स्वतंत्रता और सतत विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी और साहसिक कदम है। समय से पहले E20 के लक्ष्य को पाना सरकार के नीतिगत प्रबंधन की जीत है। लेकिन एक जीवंत लोकतंत्र और उपभोक्ता-प्रधान बाजार में किसी भी हरित क्रांति को टिकाऊ बनाने के लिए तकनीकी संवेदनशीलता और जन-आकांक्षाओं का आदर करना अनिवार्य होता है। सरकार ने E25 पर कदम रोककर और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया है, वह स्वागत योग्य है। अब आवश्यकता इस बात की है कि उद्योग जगत, नीति निमार्ता और उपभोक्ता मिलकर एक ऐसा पारदर्शी तंत्र बनाएं, जहां देश की ऊर्जा सुरक्षा और नागरिक की आर्थिक सुरक्षा दोनों एक साथ सह-अस्तित्व में समृद्ध हो सकें।

श्रद्धा के शिखर से विकास की धरातल तक, काशी में योगी का सुशासन संकल्प

-सुरेश गांधी

काशी में मंगलवार का दिन केवल एक सरकारी दौरे का दिन नहीं था, बल्कि वह दिन था जब आस्था, प्रशासन और विकास एक ही सूत्र में बंधे दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दो दिवसीय वाराणसी प्रवास के पहले दिन यह स्पष्ट संदेश दिया कि विश्व की प्राचीनतम जीवंत नगरी काशी में आध्यात्मिक गरिमा और आधुनिक विकास साथ-साथ आगे बढ़ेंगे। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मुख्यमंत्री का पूरा दिन धार्मिक आस्था, प्रशासनिक अनुशासन और विकास कार्यों की गति को समर्पित रहा। काशी पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं और कानून-व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्रावण मास के दौरान काशी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में काशीवासियों के लिए अलग दर्शन मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि स्थानीय नागरिकों को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, परिवहन निगम और रेलवे पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, निःशुल्क लॉकर, खोया-पाया केंद्र, पर्याप्त एम्बुलेंस, आपदा प्रबंधन तथा सुरक्षित यातायात जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध कराई जाएं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने, घाटों पर लाइफ जैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सीसीटीवी निगरानी को और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि जल जीवन मिशन में धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। जहां-जहां पेयजल पाइपलाइन या अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए सड़कें खोदी गई हैं, वहां तत्काल गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कराई जाए। जनता को असुविधा और दुर्घटनाओं का सामना नहीं करना चाहिए। बैठक में रोप-वे परियोजना, यूनिटी मॉल, आनंद काशी, रुद्र काशी, काशी स्पोर्ट्स सिटी, एकीकृत मंडलीय कार्यालय सहित सभी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री चौकाघाट स्थित निमार्णाधीन विद्युत सब स्टेशन पहुंचे। उन्होंने परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से विकसित हो रही काशी के लिए मजबूत विद्युत व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा गुणवत्ता से कोई समझौता न करने के निर्देश दिए।

कालभैरव और बाबा विश्वनाथ के चरणों में नमन, श्रावण की तैयारियों की गहन समीक्षा, विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण; मुख्यमंत्री बोले–₹श्रद्धा भी सुरक्षित रहे, विकास भी अविराम चले₹ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा केवल बैठकों और निरीक्षणों तक सीमित नहीं रहा। यह उस शासन दर्शन का परिचायक था, जिसमें आस्था को सम्मान, नागरिकों को सुविधा और विकास को गति–तीनों को समान महत्व दिया जाता है। कालभैरव और बाबा विश्वनाथ के चरणों में नमन से लेकर चौकाघाट के विद्युत सब स्टेशन तक पहुंचना इस बात का प्रतीक है कि नई काशी केवल मंदिरों की नगरी नहीं, बल्कि आधुनिक अधोसंरचना, सुशासन और सांस्कृतिक विरासत के संतुलित संगम के रूप में विकसित हो रही है। मुख्यमंत्री का यह दौरा उसी संकल्प को और अधिक स्पष्ट तथा मजबूत करता है

मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने, फुट पेट्रोलिंग तेज करने, पुलिसकर्मियों की समय-समय पर ड्यूटी बदलने तथा आईजीआरएस और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के साथ जनता का विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वृक्षारोपण महाअभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे जनभागीदारी का अभियान बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि काशी का विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित होना चाहिए।

बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक वाराणसी में 536 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिन पर 36,210 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं, जबकि 25,007 करोड़ रुपये की लागत वाली 191 परियोजनाएं वर्तमान में निमार्णाधीन हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और समयबद्ध पूर्णता पर विशेष बल दिया।सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए काशी के कोतवाल श्री कालभैरव मंदिर में विधिवत दर्शन-पूजन किया। मान्यता है कि कालभैरव की अनुमति के बिना काशी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और लोकमंगल की कामना करते हुए बाबा कालभैरव का आशीर्वाद प्राप्त किया।

इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने देवाधिदेव महादेव का विधिवत पूजन-अर्चन किया। श्रावण मास के आगमन से ठीक पहले बाबा विश्वनाथ के चरणों में नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जनकल्याण की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और सेवायतों ने उनका स्वागत किया। पूरे वातावरण में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के उद्घोष गूंजते रहे। दिनभर चले इस दौरे में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान, स्टाम्प एवं पंजीयन (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री रविन्द्र जायसवाल, एमएसएमई राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी, महापौर अशोक तिवारी, मंडलायुक्त एस. राजलिंगम, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

श्रावण मास केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि काशी की जीवंत सांस्कृतिक परंपरा का विराट उत्सव है। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन की चुनौती केवल भीड़ नियंत्रित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, सम्मानजनक और सहज दर्शन उपलब्ध कराना भी है। इस वर्ष की तैयारियों से स्पष्ट है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन ने परंपरा और आधुनिक प्रबंधन का संतुलित मॉडल तैयार किया है। समान दर्शन की व्यवस्था, तकनीक आधारित लाइव प्रसारण, दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं, मजबूत सुरक्षा तंत्र और व्यापक स्वास्थ्य प्रबंधन इस बात का प्रमाण हैं कि काशी केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि उत्कृष्ट व्यवस्थापन का भी उदाहरण बन रही है। श्रावण के पावन महीने में जब हर-हर महादेव के उद्घोष से संपूर्ण काशी गुंजायमान होगी, तब बाबा विश्वनाथ का धाम केवल मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति का जीवंत केंद्र बनकर विश्व को भारतीय अध्यात्म की विराटता का संदेश देगा।

पेट्रोल में एथनाल : आखिर ये माजरा क्या है ?

भारत में इन दिनों पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल का मिश्रण किये जाने यानी ई 20 पेट्रोल के इस्तेमाल से होने वाले नुक़्सान को लेकर बहस छिड़ गयी है। इसके प्रयोग से देश भर से वाहनों के इंजन खराब होने की खबरें मीडिया में आने लगी हैं। ई20 उपभोक्ता अब न केवल इसकी शिकायतें करने लगे हैं बल्कि जगह जगह इसे लेकर धरना प्रदर्शन भी होने लगे हैं। गत दिनों तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी ई 20 मिश्रित पेट्रोल के विरोध में प्रदर्शन किया गया।और इससे वाहनों को होने वाले नुक़्सान को लेकर सरकार को अवगत कराया गया। भारत में हो रहे इसके विरोध व इसके इस्तेमाल से आ रही परेशानियों व वाहनों को हो रहे कथित नुक़्सान की खबरों के बीच पड़ोसी देश भूटान ने भी भारतीय तेल कंपनियों से एथनाल मिश्रित ई 20 पेट्रोल वहां न भेजने व केवल पूर्व में भेजा जा रहा केवल शुद्ध XP100 जैसे पेट्रोल की आपूर्ति करने को कहा है। भूटान द्वारा इसका कारण यह बताया गया है कि पेट्रोल पंपों पर भण्डारण के पुराने भूमिगत फ़्यूल टैंक में ई 20 पेट्रोल के भण्डारण की वजह से पानी के रिसाव का जोखिम है जिससे एथनाल मिश्रित ईंधन खराब हो सकता है। क्योंकि इथेनॉल की प्रवृति नमी को आकर्षित करने वाली होती है और वातावरण से नमी लेने पर ईंधन की गुणवत्ता घट सकती है और इंजन में अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाके में स्टोरेज और सप्लाई श्रृंखला को आधुनिक करना भी आवश्यक होगा, जिसमें तत्काल परिवर्तन करना जोखिमपूर्ण माना गया। भूटान द्वारा अपनी आपत्ति में पहाड़ी रास्तों में वाहन के परफार्मेंस पर भी फर्क पड़ने का संदेह व्यक्त किया गया है।

भारत में भी देश भर से गाड़ियों के खराब होने,गाड़ियों की पेट्रोल टंकी के गलने व जंग लगने,माइलेज कम होने व इंजन के खराब होने तक की शिकायतें आने लगी हैं। और उधर इसी ई 20 पेट्रोल की आपूर्ति व खपत की आड़ में शुद्ध पेट्रोल यानी XP100 का मूल्य 167 रुपए प्रति लीटर तक हो गया है। एथनाल के उपयोग से केवल गाड़ियां ही खराब नहीं हो रही हैं बल्कि इसके उत्पादन में भी पानी का भी बेतहशा दुरूपयोग किया जा रहा है जिससे भविष्य में यह जलसंकट का कारण भी बन सकता है। गौरतलब है कि एथनॉल का

उत्पादन चावल ,मक्का और गन्ना आदि की फसलों से होता है। और इन सभी फसलों की पैदावार में बेतहाशा पानी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद जब इसी फसल से एथनॉल बनाया जाता है तो इसमें और भी ज्यादा पानी खर्च होता है। मिसाल के तौर पर चावल से 1 लीटर एथनॉल बनाने में लगभग 10790 लीटर पानी खर्च होता है जबकि मक्का से 1 लीटर एथनॉल बनाने में करीब 4670 लीटर पानी की खपत होती है इसी तरह गन्ने से मात्र 1 लीटर एथनाल बनाने में तकरीबन 3630 लीटर पानी लगता है। गोया पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण की नीति देश के जल बचाने के अभियान के ठीक विरुद्ध जलसंकट खड़ा करने में भी सहायक हो सकती है। जरा सोचिये कि जब E20 पेट्रोल की आपूर्ति में जल का इतना इस्तेमाल होता है तो यदि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की इच्छानुसार पेट्रोल में 85 प्रतिशत मिश्रण कर E85 की आपूर्ति की योजना पर अमल किया गया तो भारत जैसे उस देश में पानी के अकाल को कैसे टाला जा सकेगा जहां के कई इलाकों में पहले ही पीने का पानी लोगों को मयस्सर नहीं है ? हालांकि अब खबर यह भी आ रही है कि भारी विरोध के बीच केंद्र सरकार अब E25 पेट्रोल को लागू करने की योजना को फिलहाल टाल सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार अब इस ई25 बदलाव को जल्दबाजी में लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है।

देश में पेट्रोल में एथनाल के मिश्रण को लेकर कुछ जिम्मेदार लोगों के विरोधाभासी बयान भी सुनाई दे रहे हैं। इसकी वजह से आम लोगों में एथनाल के मिश्रण के प्रति अविश्वास व भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड और एग्जीक्युटिव वाईस प्रेसिडेंट विक्रम गुलाटी ने अपने एक इंटरव्यू में पहले तो यह स्वीकार किया था कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से बेशक फ़्यूल एफि शिएंसी में कुछ कमी आती है। परन्तु बाद में उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे परफॉर्मेंस के मामले में 'बेहतरीन ईंधन' भी बता डाला। इसी तरह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के बायोफ़्यूलस के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुराग सरावगी ने भी स्वीकार किया था कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ियों की माइलेज में 30 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। इतना ही नहीं बल्कि भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने गत 30 जून को सर्वोच्च न्यायलय में एक सुनवाई के दौरान अदालत को यह भी बताया कि ए-20 पेट्रोल का इस्तेमाल फिलहाल एक प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है। इस बात के सार्वजनिक होने के बाद तो लोगों में और भी आक्रोश फैल गया कि आखिर प्रयोग के तौर पर उन्हें 'गिनी पिग' अर्थात प्रयोग किये जाने वाला जीव क्यों बनाया जा रहा है। उसके बाद सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण जारी किया गया कि अटॉर्नी जनरल के हवाले से कही जा रही बातें गलत हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी एक तरह से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की बातों का समर्थन करते हुए इस बात पर नाराजगी जताई कि '3.6 करोड़ भारतीय कार मालिकों पर इसतरह के प्रयोग क्यों किए जा रहे हैं ? उन्होंने कहा कि अभी भारत में 10 में से 9 गाड़ियां ए20 के अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह नीति आम सहमति के बिना और इसके होने वाले परिणामों को समझे बगैर लागू कर दी गई है । खड़गे ने यह भी कहा, ₹हमारी गाड़ियों में इसे जबरदस्ती डालने के बाद आप राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन बदलने की इस प्रक्रिया को 'प्रयोग' नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि जब सरकार का अपना डेटा ही अभी तक तैयार नहीं है, तो नागरिकों को नुक़्सान साबित करने की चुनौती नहीं दी जा सकती । आम लोग 'गिनी पिग' नहीं हैं न ही हमारी सड़कें टेस्ट ट्रैक हैं और देश के उपभोक्ताओं की जेबें सरकार के ट्रायल का बजट नहीं हैं। खड़गे ने E20 को वापस लेने मांग करते हुये कहा कि सरकार पहले इसे प्रयोग के योग्य,स्वीकार्य व प्रमाणित ईंधन साबित करे, फिर इसे प्रयोग करने की नीति लागू करें। निश्चित रूप से पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल मिश्रण देश के वाहन धारकों के लिये फिलहाल एक समस्या बन गया है और सरकार द्वारा इसके पक्ष में दिए जा रहे तर्कों व विशेषज्ञों व इस नीति के आलोचकों द्वारा उठाये जा रहे बिंदुओं के बीच देश समझ ही नहीं पा रहा है की आखिर ये माजरा क्या है ?

– निर्मल रानी

टाटा हिताची ने राहस्ता एक्स्पो 2026 में नए एनएक्स30 और मैग्नम रॉक-ब्रेकर अटैचमेंट के साथ शिनराय प्राइम पेश किया

मुंबई। भारत की प्रमुख निर्माण उपकरण निमार्ता कंपनियों में से एक टाटा हिताची कंस्ट्रक्शन मशीनरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने राहस्ता एक्स्पो 2026 में भाग लिया। भारत के तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इस प्रदर्शनी में आधुनिक, भरोसेमंद और नई तकनीक से लैस निर्माण उपकरणों को प्रदर्शित किया।

इस वर्ष के प्रदर्शन में टाटा हिताची ने अपने दो बेहतरीन और बहुउपयोगी उपकरण एनएक्स30 मिनी एक्स्कैवेटर और मैग्नम सीरीज रॉक-ब्रेकर अटैचमेंट के साथ शिनराय प्राइम बैकहो लोडर को पेश किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से टाटा हिताची ने निर्माण कार्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, शहरी विकास और विभिन्न उपयोगिता (यूटिलिटी) प्रोजेक्ट्स के लिए ग्राहकों को अधिक भरोसेमंद, बेहतर प्रदर्शन करने वाली और जरूरत के अनुसार तैयार की गई मशीनें उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।

एनएक्स30 मिनी एक्स्कैवेटर कम और संकरी जगहों में बेहतर काम करने के लिए बनाया गया है। इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन, आसान संचालन और ईंधन बचत से कम खर्च में अधिक उत्पादकता मिलती है। मैग्नम रॉक-ब्रेकर के साथ शिनराय प्राइम बैकहो लोडर खुदाई, लोडिंग और पत्थर तोड़ने जैसे कार्यों के लिए उपयोगी है। शिनराय बेहतर प्रदर्शन, मजबूती और अधिक कार्यक्षमता प्रदान करता है, जबकि मैग्नम रॉक-ब्रेकर खदान, डिमोलिशन, सड़क निर्माण और हार्ड रॉक कार्यों में

उत्पादकता बढ़ाता है। इस अवसर पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जनरल मैनेजर मार्केटिंग ने कहा, राहस्ता एक्स्पो हमारे ग्राहकों और उद्योग क्षेत्र के भागीदारों से जुड़ने का एक बेहतरीन मंच है। भारत के तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम आधुनिक और भरोसेमंद उपकरण पेश कर रहे हैं। एनएक्स30 और मैग्नम रॉक-ब्रेकर के साथ शिनराय प्राइम हमारे उन प्रयासों का उदाहरण हैं, जिनके माध्यम से हम ग्राहकों को अधिक कुशल, विश्वसनीय और उनकी जरूरतों के अनुसार तैयार किए गए उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं। इन उपकरणों की मदद से ग्राहक देश के विकास में और अधिक आत्मविश्वास के साथ योगदान दे सकेंगे। भारत के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए टाटा हिताची जापानी तकनीक और भारतीय इंजीनियरिंग के साथ भरोसेमंद और आधुनिक उपकरण विकसित कर रही है।

पालघर जिले के 13,094 किसानों को मिलेगी कर्जमाफी, दो लाख रुपये तक का मिलेगा लाभ

पालघर (उत्तरशक्ति)। प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ से जूझ रहे किसानों को राहत देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 के तहत पालघर जिले के 13,094 किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिलेगा। जिला प्रशासन ने सभी पात्र कृषि ऋण खातों की जांच पूरी कर उनकी जानकारी राज्य सरकार के कर्जमाफी पोर्टल पर अपलोड कर दी है। योजना के अनुसार 30 सितंबर 2025 तक जिन किसानों का फसल ऋण बकाया था और जो 31 मार्च 2026 तक ऋण का भुगतान नहीं कर सके, उन्हें दो लाख रुपये तक की कर्जमाफी प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक तथा प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले पात्र किसानों को मिलेगा। जिला प्रशासन के अनुसार पात्र किसानों की सूची प्राप्त होने के बाद उसे संबंधित सेवा सहकारी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों, बैंक शाखाओं, सहायक निबंधक तथा जिला उपनिबंधक कार्यालयों में प्रकाशित किया जायेगा। इसके बाद पात्र किसानों को आपले सरकार सेवा केंद्र अथवा संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार प्रमाणीकरण कराना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्जमाफी की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जायेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर भारत के हाउसिंग मार्केट को गति दे रहे हैं

मुंबई। भारत का आवासीय बाजार एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां सिर्फ महानगरीय दर्जा नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, किफायती दरें और कनेक्टिविटी यह तय कर रहे हैं कि आवासीय मांग कहां बढ़ रही है। मैजिकब्रिक्स प्रॉपइंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से जून 2026 के बीच आवासीय मांग तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 1.2% घटी है। हालांकि, कोलकाता, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पुणे ने लगातार मजबूत होमबायर रुचि आकर्षित की, जो एक तेजी से चयनात्मक होते हाउसिंग बाजार का संकेत है। रिपोर्ट में शामिल 13 शहरों में से, कोलकाता ने सबसे मजबूत मांग वृद्धि दर्ज की, जो 7.5% QoQ रही, इसके बाद नोएडा (5.5%), ग्रेटर नोएडा (4.1%) और पुणे (2.1%) का स्थान रहा। इसके विपरीत, हैदराबाद (-6%), चेन्नई (-5.8%), नई दिल्ली (-2.9%) और बेंगलुरु (-1.8%) सहित कई स्थापित महानगरीय बाजारों में मांग में नरमी देखी गई, जबकि मुंबई (+0.6%) कमोबेश स्थिर बना रहा। यह रुझान दर्शाता है कि होमबायर्स तेजी से उन बाजारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो किफायती दरें, कनेक्टिविटी, आवास विकल्प और दीर्घकालिक मूल्य का बेहतर संतुलन प्रदान करते हैं। आपूर्ति पक्ष में भी यह उभरता विभाजन झलकता है।

सर्पदंश उपचार हेतु पालघर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार

सभी सरकारी अस्पतालों में ASV इंजेक्शन उपलब्ध, 108 एम्बुलेंस सेवा भी 24 घंटे अलर्ट

पालघर (उत्तरशक्ति)। मानसून के दौरान सर्पदंश की संभावित घटनाओं को देखते हुए जिला परिषद पालघर के स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में विशेष तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्रामीण अस्पतालों, उपजिला अस्पतालों तथा अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एंटी स्नेक वेनम (ASV) इंजेक्शन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया गया है, ताकि सर्पदंश के मरीजों को तुरंत एवं प्रभावी उपचार मिल सके।

स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों व स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। गंभीर मरीजों को बिना किसी देरी के उच्च स्तरीय अस्पतालों में पहुंचाने के लिए 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा सहित अन्य सरकारी एम्बुलेंसों को 24 घंटे तैयार रखा गया है। सभी एम्बुलेंसों को स्वच्छ, सुसज्जित और हर समय सेवा के लिए तत्पर रखने के निर्देश दिए गये हैं।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संतोष चौधरी ने नागरिकों से अपील की है कि सर्पदंश होने पर किसी भी प्रकार के घरेलू उपचार, झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र या अंधविश्वास का सहारा न लें। मरीज को बिना समय गंवाए तुरंत नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि समय पर सही चिकित्सा और ASV इंजेक्शन मिलने से मृत्यु एवं गंभीर जटिलताओं की आशंका काफी हद तक कम की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से मानसून के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा से संपर्क करें या निकटतम सरकारी स्वास्थ्य संस्था में पहुंचकर उपचार प्राप्त करें। जिला परिषद पालघर का स्वास्थ्य विभाग सर्पदंश जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क व तैयार है।

भांडुप में भारत रत्न के. कामराज नाडार की प्रतिमा का अनावरण 11 जुलाई को

मुंबई। भांडुप पश्चिम के लेक रोड स्थित शर्मा चाल में शनिवार 11 जुलाई 2026 की सुबह 10:30 बजे मुंबई नाडार संगम के नए कार्यालय का उद्घाटन और भारत रत्न के. कामराज नाडार की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया गया है। समारोह का आयोजन मुंबई नाडार संगम की ओर से किया गया है। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर पूर्व मुम्बई के सांसद . संजय दीना पाटील (भाऊ) और तिरुनलवेली के सांसद रॉबर्ट ब्रूस है। समारोह के अध्यक्ष मुंबई नाडार संगम के अध्यक्ष जे.राजा इलंगो नाडार है। समारोह का उद्घाटन जेम्स देवदासन (सचिव - बॉम्बे तिरुवल्लुवर मंत्रम) करेंगे। कार्यक्रम के संयोजक जे. राजा इलंगो नाडार ने बताया कि शनिवार की सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक भारत रत्न के. कामराज नाडार की प्रतिमा का अनावरण व मुंबई नाडार संगम के नए कार्यालय का उद्घाटन संपन्न होने के बाद ब्राइट हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज परिसर में स्थित देवदासन ऑडिटोरियम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुंबई नगर, उपनगर, थाने और नवी मुंबई के नाडार संगम के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे।

डॉक्टरों के समर्थन में विधायक रोहित पवार और आदित्य ठाकरे दोनो नेता डोंबीवली अस्पताल में डॉक्टरो से की मुलाकात

कल्याण (उत्तरशक्ति)। कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) के शास्त्रीनगर अस्पताल में डॉक्टर और महिला कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में विष्णुनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवसेना (शिंदे) के नगरसेवक रमेश म्हात्रे समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक महिला आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। डोंबीवली अस्पताल में डॉक्टरों से मिलने आदित्य ठाकरे और विधायक रोहित पवार पहुंचे। डोंबिवली के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) सुहास हेमाडे ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉ. वैभव सालुंखे की शिकायत पर एक महिला सहित कुल पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी नगरसेवक रमेश म्हात्रे के अलावा प्रमोद निकम, अक्षय करांडे और राजेश पवार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, मामले में शामिल महिला आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। एसीपी सुहास हेमाडे ने बताया कि फरार महिला आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

गौरतलब है कि शास्त्रीनगर अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों और महिला कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यह मामला काफी चर्चा में रहा। घटना के विरोध में डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों ने कड़ा विरोध जताते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की थी।

अखंड राजपुताना की मीरा-भाईंदर महिला जिलाध्यक्ष बनीं गीता सिंह

राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.पी. सिंह ने की नियुक्ति की घोषणा, समर्थकों व महिलाओं में खुशी की लहर

मीरा रोड (उत्तरशक्ति)। मीरा-भाईंदर की सक्रिय समाजसेविका तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाली गीता सिंह को अखंड राजपुताना संगठन की मीरा-भाईंदर महिला जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अखंड राजपुताना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.पी. सिंह ने गीता सिंह के नाम की औपचारिक घोषणा करते हुए उन्हें महिला जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा। उनकी नियुक्ति की घोषणा के साथ ही उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मीरा-भाईंदर क्षेत्र की महिलाओं में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। नवनियुक्त महिला जिलाध्यक्ष गीता सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.पी. सिंह ने उन पर जो विश्वास जताया है, वह उस विश्वास पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के साथ-साथ समाज हित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में कमलेश सिंह, नितेश सिंह, ओम प्रकाश सिंह सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

क्या अवैध टैक्सी-रिक्शा ऐप आधारित परिवहन पर होगी कार्रवाई?

चांदीवली के विधायक दिलीप लांडे ने विधानसभा में उठाया मुद्दा

मुंबई। राज्य सरकार की किसी भी प्रकार की अनुमति के बिना, विशेष रूप से मुंबई में ऐप के माध्यम से संचालित हो रही अवैध टैक्सी और ऑटो-रिक्शा सेवाओं के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिलीप लांडे ने विधानसभा में की।

विधायक लांडे ने कहा कि इन अवैध ऐप आधारित परिवहन सेवाओं के कारण महिलाएं और विद्यार्थी असुरक्षित हो गए हैं। साथ ही, नियमों का पालन कर वैध रूप से टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चलाने वाले हजारों गरीब चालकों और उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि अधिकृत टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालक सरकार के सभी नियमों का पालन करते हैं, आवश्यक परमिट लेते हैं और सरकारी राजस्व का भुगतान करते हैं। इसके विपरीत, अवैध ऐप आधारित परिवहन सेवाओं की न तो कोई वैध सरकारी अनुमति है और न ही उनका विधिवत पंजीकरण किया गया है, जिससे वैध चालकों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। विधायक लांडे ने यह भी कहा कि सबसे गंभीर चिंता महिलाओं और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर है। इन वाहनों के चालकों का पुलिस सत्यापन नहीं होता, उनके वाहनों का बीमा नहीं कराया जाता और उनके पास आवश्यक सरकारी लाइसेंस भी नहीं होते। ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की कि इस पूरे मामले की जांच कर अवैध परिवहन सेवाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तथा नागरिकों के साथ हो रही धोखाधड़ी पर रोक लगाई जाए।

भिवंडी में मेधावी छात्रों के सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि होंगे यादव संघ मुंबई के अध्यक्ष अजय यादव

भिवंडी। भिवंडी में यदुवंशी समाज सेवा संस्था द्वारा 10 जुलाई शुक्रवार को हो रहे मेधावी छात्रों के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यादव संघ मुंबई के अध्यक्ष अजय यादव उपस्थित रहेंगे। बतादें कि यदुवंशी समाज सेवा संस्था के राष्ट्रीय सचिव व वरिष्ठ पत्रकार आचार्य सूरजपाल यादव के जन्मदिन पर हर वर्ष की भांति यदुवंशी समाज सेवा संस्था के भिवंडी जिलाध्यक्ष लालबहादुर यादव की अगुवाई में वरालदेवी चौक स्थित श्री अयप्पा स्वामी मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर संघ के भिवंडी महासचिव राजेश यादव, कोषाध्यक्ष राज यदुवंशी, कार्याध्यक्ष लल्लन यादव, उपाध्यक्ष संतलाल यादव, सदस्यों में संदीप कुमार यादव, दीपक यादव, लवधारी यादव आदि कार्यकताओं की मुख्य भूमिका रहेगी। इस अवसर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत बलीराम यादव, रा. महासचिव सभाजीत यदुवंशी, रा. कोषाध्यक्ष विवेक यादव, रा.कार्याध्यक्ष जयसरोज यादव, शिक्षा समिति अध्यक्ष सभाजीत एस यादव, रा. सचिव दीनानाथ यादव आदि पदाधिकारी उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभायेंगे। संघ के राष्ट्रीय सचिव आचार्य सूरजपाल यादव ने सभी यादव समाज के लोगों से अपील की है कि इस कार्यक्रम में 10वीं, 12वीं व उच्च शिक्षा में उत्तीर्ण अपने बच्चों की अंक तालिका के साथ उपस्थित रहकर बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित प्रोत्साहित करने में सहयोग करें।

खेती के दस्तावेज अपडेट रखें, तभी मिलेगा समय पर बिजली परियोजनाओं का मुआवजा : रेसोनिया लिमिटेड

-आचार्य सूरजपाल यादव

भिवंडी। महाराष्ट्र में तेजी से विकसित हो रहे बिजली प्रसारण (ट्रांसमिशन) नेटवर्क के तहत किसानों की जमीन पर ट्रांसमिशन टावर और बिजली लाइनें स्थापित की जा रही हैं। ऐसे में प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलने में होने वाली देरी से बचने के लिए अपनी जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज अद्यतन रखना बेहद जरूरी है। यह जानकारी भारत की अग्रणी बिजली प्रसारण कंपनी रेसोनिया लिमिटेड के उपाध्यक्ष निनाद पितले ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में हरित ऊर्जा और बिजली प्रसारण परियोजनाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे उद्योगों, कृषि, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक भरोसेमंद बिजली आपूर्ति मिलेगी। जिन किसानों की जमीन से बिजली लाइन गुजरती है या जहां ट्रांसमिशन टावर स्थापित किए जाते हैं, वे शासन के नियमानुसार मुआवजे के पात्र होते हैं। निनाद पितले ने कहा कि कई बार मुआवजे की राशि उपलब्ध होने के बावजूद उसका भुगतान समय पर नहीं हो पाता। इसकी मुख्य वजह कंपनी की देरी नहीं, बल्कि जमीन के राजस्व अभिलेखों और दस्तावेजों से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। सातबारा (7/12) रिकॉर्ड अपडेट न होना, वारिसों की प्रविष्टि लंबित होना, स्वामित्व विवाद, सीमांकन या न्यायालयीन मामले, अधूरे दस्तावेज तथा बैंक खाते की जानकारी में त्रुटियां जैसी वजहों से भुगतान प्रक्रिया प्रभावित होती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपने सातबारा, वारिस पंजीकरण और अन्य भूमि संबंधी दस्तावेज समय-समय पर अपडेट रखें, ताकि कानूनी जांच पूरी होने के बाद मुआवजा बिना किसी अनावश्यक विलंब के सीधे उनके खाते में जमा किया जा सके। रेसोनिया लिमिटेड वर्तमान में पालघर और भिवंडी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बिजली प्रसारण परियोजना पर कार्य कर रही है। कंपनी ने किसानों से परियोजना, मुआवजा प्रक्रिया या आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 203 5844 पर संपर्क करने की अपील की है। कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि किसानों के सभी प्रश्नों का समाधान और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

जेनेरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस ने 'सुनहरा पेंशन प्लान' लॉन्च किया

मुंबई। जेनेरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, निजी क्षेत्र की एक प्रमुख लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ने 'सुनहरा पेंशन प्लान' लॉन्च किया है। यह एक पार्टिसिपेटिंग, नॉन-लिंक्ड, पेंशन और बचत-आधारित जीवन बीमा योजना है। इसका उद्देश्य पॉलिसीधारकों को एक सेवानिवृत्ति कोष बनाने में मदद करना है ताकि उनका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। यह फंड मुख्य रूप से जीवन बीमा के फायदों के अलावा, कल्याण सेवाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराता है, जो जेनेरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस की अपने पॉलिसीधारकों को बेहतर अनुभव देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जेनेरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस, वैश्विक बीमा अग्रणी - जेनेरली और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक संयुक्त उद्यम है, जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता और स्थानीय बैंकिंग की विरासत का एक अद्भुत मेल है। एक पार्टिसिपेटिंग योजना होने के नाते, सुनहरा पेंशन प्लान में पहले साल से ही धन उपार्जित होने लगता है और पॉलिसीधारक लंबे समय तक इस चक्रवृद्धि बढ़त का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत आपको 5 से 40 साल तक की पॉलिसी अवधि चुनने का विकल्प मिलता है, जो हर उम्र के लोगों के लिए बिलकुल उपयुक्त उत्पाद है। साथ ही, मृत्यु या वेस्टिंग (पॉलिसी की अवधि पूरी होने) पर निश्चित लाभ भी मिलते हैं। इस योजना को अपनाकर आप आर्थिक मुसीबत के समय आंशिक रूप से नकदी रकम निकाल सकते हैं। पॉलिसी की अवधि के दौरान न केवल सिंगल पे, लिमिटेड पे या रेगुलर पे जैसे कई प्रीमियम भुगतान विकल्प मिलते हैं बल्कि आप राइडर्स का विकल्प चुनकर अपनी सुरक्षा बढ़ा भी सकते हैं, जिससे यह एक विस्तृत और लचीला सेवानिवृत्ति योजना बन जाती है। इस योजना की अहमियत के बारे में बताते हुए, आलोक रुंगटा, एमडी और सीईओ, जेनेरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस, ने कहा, बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में जीवन बीमा न केवल जीवन सुरक्षा बल्कि लंबे समय में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। भारतीयों के दीर्घ जीवन और औपचारिक पेंशन तंत्र की अपर्याप्तता को देखते हुए, सेवानिवृत्ति योजना के लिए एक अनुशासित और व्यवस्थित नजरिए से पहल करने की जरूरत है। जेनेरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस में, हमारा मानना है कि लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए पहले से तैयार करना आवश्यक है। 'सुनहरा पेंशन प्लान' इसी मकसद से बनाया गया है। यह पार्टिसिपेटिंग उत्पाद की खूबियों और दीर्घकालिक बचत की स्थिरता का एक बेहतरीन समागम है, जो ग्राहकों को एक स्थायी सेवानिवृत्ति कोष बनाने में सहायता करता है। हम ऐसे उत्पाद लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं जो आर्थिक मजबूती बढ़ाने के साथ-साथ ग्राहकों को जीवन के हर पड़ाव पर भरोसा और सुरक्षा प्रदान करे। अनुमान है कि भारत की बुजुर्ग आबादी 2022 के 10.5% से दोगुनी होकर 2050 तक 20.8% हो जाएगी, जबकि देश में पेंशन परिसम्पत्तियां विकसित बाजारों की तुलना में मात्र 17% GDP हैं।

भारथक्लाउड ने अपने पहले ब्रांड मैस्कॉट बादल का अनावरण किया, भारत के सॉवरेन एआई क्लाउड विजन को और मजबूत किया

मुंबई। भारत के सॉवरेन एआई क्लाउड सेवा प्रदाता भारथक्लाउड ने आज अपने पहले ब्रांड मैस्कॉट बादल का अनावरण किया। यह कंपनी की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और पूरे भारत में व्यवसायों तथा उपयोगकताओं के लिए क्लाउड और एआई तकनीकों को अधिक सहज, जुड़ावपूर्ण और सुलभ बनाने की उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। जैसे-जैसे भारथक्लाउड व्यवसायों, संस्थानों, स्टार्टअप्स और सरकारी इकोसिस्टम के बीच अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है, बादल को एक अत्यधिक तकनीकी श्रेणी को मानवीय स्वरूप प्रदान करने तथा प्रत्येक चरण में ग्राहकों के लिए क्लाउड अपनाने की यात्रा को सरल बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह लॉन्च ऐसे समय में भी हुआ है, जब कंपनी के ग्राहकों और रणनीतिक साझेदारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तथा वह विभिन्न हितधारक समुदायों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास कर रही है। भारत की देशभक्ति की भावना तथा क्लाउड तकनीक के प्रतीकों से प्रेरित बादल, संप्रभुता, विश्वास, सुरक्षा तथा भारथक्लाउड द्वारा मेड इन इंडिया होने के गौरव के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। भारथक्लाउड के लिए मैस्कॉट चुनने के पीछे का विचार क्लाउड तकनीकी अवसंरचना और उपयोगकताओं के बीच एक संबंध स्थापित करना है। भारथक्लाउड के सह-संस्थापक राहुल तक्कल्लापल्ली ने कहा, क्लाउड तकनीक, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, कभी भी भय उत्पन्न करने वाली नहीं लगनी चाहिए। बादल के माध्यम से हम भारथक्लाउड को एक मानवीय पहचान दे रहे हैं और क्लाउड तथा एआई से जुड़ी बातचीत को अधिक आकर्षक, समावेशी और सुलभ बना रहे हैं। जैसे-जैसे भारत अपना डिजिटल भविष्य निर्मित कर रहा है, हमारा मानना है कि तकनीक को सहज, सुरक्षित और स्थानीय आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं से गहराई से जुड़ा रहना चाहिए।

बादल सभी ग्राहक ऑनबोर्डिंग गतिविधियों, डिजिटल अभियानों, शैक्षणिक गतिविधियों, उद्योग से संबंधित आयोजनों तथा सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेगा। आकर्षक स्टोरीटेलिंग और प्रभावी प्रभाव के साथ, बादल, क्लाउड जर्नी सिंप्लिफाइड के बैनर तले व्यवसायों और उपयोगकर्ताओं को उनकी क्लाउड यात्रा में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। भारथक्लाउड की सह-संस्थापक एवं मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी पद्मा रेड्डी सामा ने कहा, केवल एक मैस्कॉट होने से आगे बढ़कर, बादल का परिचय भारथक्लाउड द्वारा अपने ग्राहकों के साथ एक और गहरा भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने तथा भारत के सॉवरेन एआई क्लाउड सेवा प्रदाता के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत करने का एक प्रयास है। वर्तमान परिदृश्य में यह और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जहां अधिकांश कंपनियां वैश्विक हाइपरस्केलर्स के प्रभुत्व वाले अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में कार्य करती हैं। यह लॉन्च भारथक्लाउड की व्यापक ब्रांड-निर्माण और मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा है, जिसमें ग्राहक सहभागिता पहल, बी2बी आउटरीच, डिजिटल अभियान और प्रत्यक्ष अनुभव शामिल हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि कंपनी अपने उपभोक्ता-केंद्रित प्रयासों को और गहरा करने का इरादा रखती है, क्योंकि क्लाउड तकनीकें अब व्यावसायिक वातावरण से आगे बढ़कर भी अधिक प्रासंगिक होती जा रही हैं। आगे बढ़ते हुए, भारथक्लाउड समर्पित सोशल मीडिया श्रृंखलाओं, शैक्षणिक कार्यक्रमों, स्कूल सहभागिता, लघु फिल्मों, इंटरैक्टिव अनुभवों तथा अन्य पहलों के माध्यम से बादल का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिन्हें सॉवरेन क्लाउड समाधानों के प्रति बढ़ती समझ और स्वीकार्यता विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। बादल के लॉन्च के साथ, भारथक्लाउड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की धारणा को एक जटिल तकनीक से बदलकर एक मानवीय, विश्वसनीय और भारतीय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में स्थापित करने की आकांक्षा रखता है।

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय :
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामीः शरद फागुराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजुरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

युवाओं को रोजगार से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य समाजवादी सरकारों ने किया: मोहम्मद अरशद खान

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। पीडीए भवन, कटघरा में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को सम्मान, पहचान और रोजगार से जोड़ने का सबसे बड़ा कार्य मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुआ।

उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकारों ने उर्दू शिक्षकों और उर्दू ट्रांसलेटर्स की व्यापक भर्ती कराकर हजारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया। साथ ही बड़ी संख्या में मदरसों को मान्यता प्रदान की गई तथा अनेक मदरसों को सहायता प्राप्त (एडेड) श्रेणी में शामिल किया गया, जिससे हजारों उर्दू शिक्षकों और उनके परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता मिली। उन्होंने इसे उर्दू भाषा को सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल बताया।

मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि समाजवादी सरकार ने शासन और प्रशासन में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के अनेक प्रतिनिधियों को विधानसभा का टिकट दिया गया

और सरकार में दस से अधिक मंत्रियों को शामिल कर राजनीतिक भागीदारी को मजबूत किया गया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जावेद उस्मानी को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया तथा मुस्लिम अधिकारियों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा सामाजिक न्याय, समान अवसर और संविधान की मूल भावना पर आधारित है। इसी कारण पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, नौजवान, महिलाएं और वंचित वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं।

वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समाज सहित न्यायप्रिय एवं लोकतांत्रिक सोच रखने वाले मतदाता समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे और अखिलेश यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का जनादेश देंगे।

प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की राजनीति नफरत नहीं, बल्कि भाईचारा, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और सर्वसमावेशी विकास की राजनीति है तथा यही विचार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

कृषक विकास समित नि:शुल्क वृद्धाश्रम सैय्यद अलीपुर में लगा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर

मेडिकल कालेज जौनपुर द्वारा किया गया आयोजन

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के प्रधानाचार्य प्रो0 आर0 बी0 कमल के दिशा निर्देश में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो0 ए0ए0 जाफरी एवं जनरल मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डा0 विनोद कुमार के कुशल मार्ग दर्शन में दिनांक 08 जुलाई, 2026 को कृषक विकास समित निःशुल्क वृद्धाश्रम सैय्यद अलीपुर, सदर जौनपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।

यह स्वास्थ्य शिविर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जनहित एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित होकर वृद्धाश्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने हेतु मेडिकल कालेज जौनपुर प्रशासन से अनुरोध किया। परिषद के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सको की टीम को भेजा गया जिसमें नेत्र रोग विभाग, जनरल मेडिसिन विभाग, क्षय एवं वक्ष रोग विभाग (टीबी एवं चेस्ट), सामुदायिक चिकित्सा विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग सहित विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चिकित्सकों ने रोगियों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श प्रदान करते हुए आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया। शिविर में रक्तचाप, मधुमेह एवं अन्य सामान्य रोगों की जांच कर मरीजों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया।

मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो० आर० बी० कमल ने वृद्धाश्रम में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के वरिष्ठ नागरिक हमारे अनुभव, संस्कृति एवं मूल्यों के अमूल्य धरोहर हैं। उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। उन्होंने शिविर में सहभागी चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के सेवा कार्य चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की सामाजिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं तथा भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो० ए0 ए0 जाफरी ने वृद्धाश्रम में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे शिविर समाज के वरिष्ठ नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों की नियमित स्वास्थ्य जांच, समय पर उपचार तथा आवश्यक परामर्श से उनके जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य शिविर का आयोजन विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ उनके निकट ही उपलब्ध कराया जा सके।

इस अवसर पर चिकित्सक डा0 अमित पटेल, डा0 नितेश कुमार यादव, डा0 निहारिका, डा0 अक्षय सिंह, डा0 संदीप सिंह एवं फार्मासिस्ट व कर्मचारी तथा गिरिजेश राय (संरक्षक), हरिशंकर (प्रधान), रविकुमार (केयर टेकर), महिमा चौबे (केयर टेकर), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय सदस्य हर्षवर्धन, प्रखर, अक्षत व अर्जुन आदि लोग उपस्थित रहें।

नौकरी छोड़ मत्स्य पालन अपनाया, जौनपुर के राहुल राय ने रचा सफलता का नया कीर्तिमान

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनपद के विकास खंड करंजाकला के ग्राम आरा निवासी राहुल रॉय ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर जिले के किसानों और युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गए हैं। निजी क्षेत्र की लाखों रुपये की नौकरी छोड़कर उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन शुरू किया और आज लाखों रुपये की आय अर्जित करने के साथ-साथ ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं।

राहुल रॉय ने अपने चाचा के प्रोत्साहन से छोटे निजी तालाब से मत्स्य पालन की शुरूआत की थी। वर्तमान में वह 108.906 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले विभागीय जलाशय 'आरा ताल' का ठेका लेकर बड़े पैमाने पर मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं। मत्स्य विभाग द्वारा समय-समय पर उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन एवं वैज्ञानिक सलाह दी जाती रही, जिसके चलते उनके उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में उन्होंने दो उत्पादन चक्रों के दौरान लगभग 1000 कुंतल पंगेशियस, 200 कुंतल रूपचंदा, 50 कुंतल रोहु, 50 कुंतल भाकुर तथा 30 कुंतल मृगल मछली का उत्पादन किया। इस उत्पादन से करीब एक करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि उनकी वार्षिक शुद्ध आय 70 से 75 लाख रुपये तक पहुंच गई है।

मत्स्य विभाग के अनुसार राहुल रॉय ने प्रारंभिक दौर में जहां केवल 20 कुंतल आईएमसी मछली का उत्पादन किया था, वहीं वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर अब उनका वार्षिक उत्पादन लगभग 1400 कुंतल तक पहुंच गया है। राहुल रॉय की सफलता से आसपास के गांवों के लोग भी मत्स्य पालन की ओर प्रेरित हो रहे हैं। उनके इस उद्यम से 8 से 10 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।

मत्स्य विभाग ने राहुल रॉय की उपलब्धि को किसानों के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि वैज्ञानिक तकनीक, विभागीय सहयोग और सतत मेहनत से मत्स्य पालन को अत्यंत लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है। राहुल रॉय की सफलता इसी का जीवंत उदाहरण है।

जौनपुर में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ, शिक्षकों को मिले स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ एवं विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रति विद्यार्थी 1200 रुपये की धनराशि हस्तांतरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चन्द्र यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, नगर पालिका अध्यक्ष मनोरमा मौर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया।

इस दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के 10 शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, स्पेशल एजुकेटर एवं रसोइयों तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के पांच शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक

कैशलेस चिकित्सा योजना के प्रतीकात्मक कार्ड प्रदान किए गए।

राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों एवं उनके परिवारों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा यह योजना गुरुजनों के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि इस योजना का लाभ शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, विशेष शिक्षकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षकों, रसोइयों तथा उनके आश्रितों को मिलेगा, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी की खरीद के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी गई है। उन्होंने अभिभावकों से इस राशि का उपयोग बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं पर ही करने की अपील की। साथ ही बताया कि जनपद निपुण भारत योजना में प्रथम स्थान पर है और सभी परिषदीय विद्यालयों में प्रत्येक माह अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित कर विद्यार्थियों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

12 जुलाई को जौनपुर में लगेंगे 60.73 लाख पौधे

डीएम ने दिए महाअभियान की तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में वृक्षारोपण महाअभियान-2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में 12 जुलाई को होने वाले अभियान के लिए विभागवार लक्ष्य, पौधरोपण स्थलों, पौधों की उपलब्धता, गड्ढों की खुदाई, पौधों के उठान, जियो टैगिंग तथा संरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 12 जुलाई को उत्सवपूर्ण वातावरण में वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ आयोजित किया जाएगा। इसके तहत जनपद जौनपुर को 60 लाख 73 हजार 400 पौधे लगाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर अभियान को पूरी तैयारी, समन्वय और जवाबदेही के साथ सफल बनाया जाए। कृषि विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) तथा अधिक लक्ष्य वाले विभागों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए।

डीएम ने कहा कि पौधरोपण स्थलों का पूर्व सत्यापन, गड्ढों की तैयारी, पौधों की उपलब्धता, सिंचाई, जियो टैगिंग और नियमित निगरानी की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए। साथ ही अभियान की निगरानी के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक पौधे के संरक्षण, सुरक्षा और नियमित देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि वृक्षारोपण का उद्देश्य सफल हो सके। वन विभाग को नोडल विभाग के रूप में सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) अजय अंबष्ट, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा, जिला विकास अधिकारी, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी दिव्या, उप जिलाधिकारी सदर योगिता सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

अपराधियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, जौनपुर में 150 से अधिक शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनपद में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले में 150 से

अधिक शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई चल रही है। इसके लिए सभी थाना क्षेत्रों में संबंधित लाइसेंस धारकों का सत्यापन कराया जा रहा है और सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सत्यापन पूरा होने के बाद संबंधित लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुना जाएगा। नियमानुसार सुनवाई के उपरांत जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के पर्याप्त आधार मिलेंगे, उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। अधिकारियों के अनुसार भविष्य में भी ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

विशेष लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान को लेकर जिला न्यायाधीश ने दिए आवश्यक निर्देश

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशील कुमार शशि की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों की बैठक दीवानी न्यायालय के मीटिंग हाल में आयोजित की गई। बैठक में आगामी विशेष लोक अदालत 'समाधान समारोह', धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित विशेष लोक अदालत तथा 'राष्ट्र के नाम मध्यस्थता अभियान 2.0' के सफल आयोजन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर चर्चा की गई।

जनपद न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समाधान समारोह के लिए अधिक से अधिक लंबित मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण कराया जाए। उन्होंने इसके लिए 10 जुलाई, 22 जुलाई और 7 अगस्त 2026 को प्रस्तावित बैठकों में पक्षकारों के बीच प्रभावी मध्यस्थता कराने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली धारा 138 एनआई एक्ट विशेष लोक अदालत के लिए संबंधित मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस जारी करने को कहा गया।

जनपद न्यायाधीश ने कहा कि मध्यस्थता विवादों के समाधान का सरल और प्रभावी माध्यम है। इससे पक्षकारों के बीच आपसी कटुता समाप्त होती है और सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम होता है। उन्होंने अधिकारियों को 'राष्ट्र के नाम मध्यस्थता अभियान 2.0' का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आम लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सहित सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।

जीआरपी जौनपुर की बड़ी सफलता: 88 गुम मोबाइल बरामद, 55 मालिकों को लौटाए

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। रेल यात्रियों के गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने में जीआरपी जौनपुर को बड़ी सफलता मिली है। सर्विलांस सेल और पुलिस टीम के संयुक्त प्रयास से ट्रेनों में यात्रा के दौरान खोए 88 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनमें से 55 मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए, जबकि शेष मोबाइलों को उनके स्वामियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है।

यह अभियान पुलिस महानिदेशक रेलवे लखनऊ प्रकाश डी., पुलिस महानिरीक्षक रेलवे जोन प्रयागराज एन. कोलान्ची, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग प्रयागराज प्रशांत वर्मा तथा पुलिस उपाधीक्षक रेलवे वाराणसी कुंवर प्रभात सिंह के निर्देशन में चलाया गया। थाना जीआरपी जौनपुर के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार गौड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम और सर्विलांस सेल ने लगातार प्रयास कर यह सफलता हासिल की।

जीआरपी के अनुसार बरामद

मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत करीब 19 लाख रुपये है। मोबाइल वापस पाने के लिए विभिन्न जनपदों और अन्य राज्यों से पहुंचे लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। लोगों ने अपना खोया मोबाइल मिलने पर जीआरपी जौनपुर की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए पूरी टीम का आभार व्यक्त किया।

जीआरपी जौनपुर ने बताया कि जिन मोबाइल फोन की बरामदगी अभी शेष है, उन्हें भी जल्द खोजकर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा जाएगा। इस अभियान में थाना प्रभारी सुनील कुमार गौड़, उपनिरीक्षक हरिकेश, शिवपूजन यादव, बुजेश कुमार, सर्विलांस प्रभारी राधा मोहन द्विवेदी, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार, कांस्टेबल रामप्रवेश कुमार, कांस्टेबल मनीष कश्यप तथा महिला आरक्षी किरण लता की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

डीएम ने किया एनएच-135ए जौनपुर-शाहगंज सेक्शन का निरीक्षण, गुणवत्ता और समयबद्ध निर्माण के दिए निर्देश

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने निमार्णाधीन एनएच-135ए (पैकेज-2) जौनपुर-शाहगंज सेक्शन का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण, किसानों को मुआवजा भुगतान तथा विभिन्न विभागीय स्वीकृतियों की स्थिति की समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि परियोजना के सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर, उच्च गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं, ताकि आमजन को शीघ्र बेहतर

सड़क सुविधा का लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि यह मार्ग वाराणसी और अयोध्या को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है, जिसकी उपयोगिता और महत्व काफी अधिक है। इसलिए निर्माण कार्य में गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और समयबद्धता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित 261 करोड़ रुपये के सापेक्ष अब तक 236 करोड़ रुपये किसानों को भुगतान किए जा चुके हैं। इस अवसर पर परियोजना निदेशक (प्रोजेक्ट डायरेक्टर) एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

'मिशन सेफ फ्यूचर' अभियान के तहत कड़ी करर्वाई शुरू

फिटनेस/परमिट फेल 06 स्कूली वाहन थाने में सीज एवं 15 वाहनों का हुआ चालान

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। परिवहन

आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा 'मिशन सेफ फ्यूचर' अभियान के तहत 15 जुलाई, 2026 तक फिटनेस/परमिट फेल स्कूली वाहनों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुपालन में 08 जुलाई 2026 को सहायक सम्भागीय अधिकारी (प्रवर्तन) सत्येन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर स्कूली बसों की जॉच की गयी। जिसमें परमिट, फिटनेस एवं अन्य प्रपत्र न मिलने पर 06 बसों को सीज कर दिया जबकि 15 बसों का चालान किया गया। ए0आर0टी0ओ0 (प्रवर्तन) द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बसो में परमिट, फिटनेस या सुरक्षा उपकरण न होने पर उन्हें सीज किया जायेगा।

उक्त अभियान रामपुर थाना, खुटहन थाना, चन्दवक, मछलीशहर थाने के सहयोग से ऐसे स्कूली वाहन जिनके प्रपत्र फेल है के विरूद्ध अभियान चलाया गया। उक्त के साथ ए0आर0टी0ओ0 द्वारा जनपद के समस्त प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य/वाहन स्वामी से अनुरोध किया गया है कि जिन विद्यालयों में वाहनों से बच्चों का आवागमन होता है और उनका फिटनेस एवं परमिट समाप्त हो गया है तो वे तत्काल फिटनेस/परमिट बनवा लें। यद्यपि बिना परमिट के जो भी वाहन संचालित पायी जायेगी उनके विरूद्ध चालान/निरूद्ध की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

19 दिन बाद खत्म हुआ सौम्या बिंद का धरना, प्रशासन के आश्वासन पर लिया बड़ा फैसला

दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड में कार्रवाई की मांग को लेकर चल रहा था आंदोलन, डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपने के बाद समाप्त हुआ धरना

प्रियेश गुप्ता रुद्रा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर चल रहा धरना मंगलवार को समाप्त हो गया। मृतक आजाद बिंद की बहन सौम्या बिंद ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के बाद प्रशासन से मिले आश्वासन पर अपना धरना समाप्त करने की घोषणा की।

बताया गया कि प्रशासन की ओर से मामले में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद सौम्या बिंद

ने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया।

गौरतलब है कि आजाद बिंद हत्याकांड को लेकर सौम्या बिंद पिछले कई दिनों से आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठी थीं। मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने और सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद यह धरना समाप्त हो गया। अब परिजनों और समर्थकों की निगाहें प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन पर टिकी हैं और मामले में आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।

रील बनाने से रोकने पर किशोरी द्वारा आत्महत्या की आशंका, नहर में मिली लाश

चंदौली(उत्तरशक्ति)। जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र के आलूमिल नई बस्ती स्थित गंगा नहर में बुधवार को 15 वर्षीय किशोरी खुशबू का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में परिजनों द्वारा रील बनाने से मना करने पर डांट से आहत होकर किशोरी के नहर में छलांग लगाने की आशंका है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

शिक्षा की नींव से विकसित भारत का शंखनाद, शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ

वाराणसी। काशी की आध्यात्मिक चेतना से एक बार फिर शिक्षा, संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश पूरे प्रदेश में गूंजा। बड़ालालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर (टीएफसी) से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी योजनाओं का शुभारंभ किया, जिनका केंद्र केवल सरकारी व्यवस्था नहीं बल्कि भविष्य का भारत था। मंच से मुख्यमंत्री का स्वर केवल घोषणा का नहीं, बल्कि उस राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक था जिसमें शिक्षा को राष्ट्रनिर्माण का सबसे सशक्त माध्यम माना गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। यह केवल शिक्षकों या अभिभावकों का नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।श् उनके इस संदेश ने कार्यक्रम को सरकारी औपचारिकता से ऊपर उठाकर सामाजिक आंदोलन का स्वरूप दे दिया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के एक करोड़ दस लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के खातों में 1320 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना का शुभारंभ किया गया, जिससे प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा विद्यालयों के कर्मचारी तथा मध्यान्ह भोजन योजना के रसोइये और उनके परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में आएंगे। समारोह में शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच महत्वपूर्ण एमओयू का भी आदान-प्रदान हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी कक्षाओं में आकार लेता है। बच्चे कोरा कागज होते हैं और शिक्षक उनके व्यक्तित्व के प्रथम शिल्पकार। यदि प्रारंभिक शिक्षा की नींव मजबूत होगी तो राष्ट्र की इमारत भी उतनी ही सुदृढ़ बनेगी। उन्होंने कहा, श्मजबूत नींव पर ही मजबूत भवन खड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे बच्चों की शिक्षा और संस्कार मजबूत होंगे तो विकसित और आत्मनिर्भर भारत का सपना स्वतः साकार होगा।श् मुख्यमंत्री ने निपुण भारत अभियान को शिक्षा सुधार का आधार बताते हुए कहा कि अब शिक्षा केवल परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत क्षमता को विकसित करने का माध्यम बनेगी। हर विद्यार्थी अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार पारंगत बने, यही अभियान का लक्ष्य है। उन्होंने शिक्षकों का आह्वान करते हुए कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की प्रयोगशाला होने चाहिए। विद्यालय का वातावरण स्वच्छ, सुंदर, अनुशासित और प्रेरणादायी हो, ताकि वहां प्रवेश करने वाला प्रत्येक बच्चा अपने भीतर भविष्य के भारत की झलक महसूस कर सके। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का समन्वय ही आने वाले भारत की वास्तविक शक्ति बनेगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बदली हुई तस्वीर का उल्लेख करते हुए कहा कि कभी उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन पिछले नौ वर्षों में डबल इंजन सरकार के प्रयासों ने प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता और आज उत्तर प्रदेश ने नकलमुक्त परीक्षा प्रणाली स्थापित कर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रनिर्माण में भारतीय चिंतन की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि आचार्य चाणक्य और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे महापुरुष हमारे आदर्श होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे आदर्शों पर चलने वाला समाज इतना सक्षम बनता है कि कोई भी शक्ति उसकी ओर टेढ़ी नजर से देखने का साहस नहीं कर सकती। उन्होंने प्रोजेक्ट अलंकार का उल्लेख करते हुए बताया कि माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने व्यापक निवेश किया है। आधुनिक कक्षाएं, बेहतर प्रयोगशालाएं, स्वच्छ परिसर और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला बन रही हैं। कार्यक्रम में शुभारंभ की गई मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना को शिक्षकों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक शिक्षक के लिए वार्षिक प्रीमियम वहन करेगी। सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लगभग 1900 से अधिक उपचार पैकेजों के माध्यम से गंभीर बीमारियों, हृदय रोग, कैंसर, किडनी रोग और जटिल सर्जरी जैसी सुविधाएं कैशलेस उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से 15 शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी प्रदान किए। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुए समझौते के माध्यम से लाखों शिक्षकों एवं कर्मचारियों को जीवन बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्थायी विकलांगता सुरक्षा, एयर एक्सीडेंट कवर तथा आकस्मिक परिस्थितियों में बच्चों की शिक्षा और बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। समारोह में स्वच्छ एवं हरित विद्यालय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 12 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को भी सम्मानित किया गया।

बारिश के दौरान समस्याओं एवं हेल्पलाइन के व्यापक प्रचार-प्रसार पर अतिरिक्त जिल्हा अधिकारी से चर्चा

ठाणे (उत्तरशक्ति)। वर्षा ऋतु के दौरान नागरिकों को होने वाली समस्याओं के समाधान और आपातकालीन सहायता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आज ठाणे के अतिरिक्त जिल्हा अधिकारी हरिशचंद्र पाटील से सौजन्य भेंट कर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बारिश के समय जलभराव, यातायात बाधित होने जैसी परिस्थितियों में नागरिकों तक प्रशासन की सहायता समय पर पहुँचाने तथा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बेहतर समन्वय के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने पर भी विचार-विमर्श हुआ। इस अवसर पर शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं उत्तर भारतीय मोर्चा के नेता प्रमोद अशोक दुबे तथा डीएलजी फिल्म के निमार्ता दीपक गुप्ता भी उपस्थित रहे। बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि मानसून के दौरान प्रशासनिक सेवाओं को अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाकर आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

माटुंगा में बारिश और तेज हवाओं से पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ी

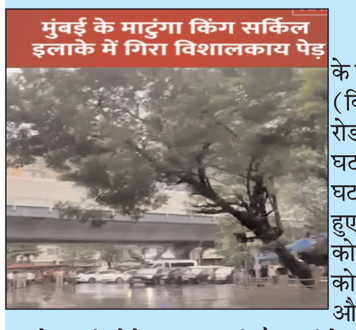

-राजकुमार अग्रहरि

मुंबई (उत्तरशक्ति)। बारिश के कारण माटुंगा के महेश्वरी उद्यान (किंग्स सर्कल) और नूर महल रोड पर विशालकाय पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं से कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन राहत की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। यातायात को सामान्य करने के लिए बीएमसी और दमकल विभाग रास्ते से पेड़ हटाने कार्य जोरों पर कर रही है।मुंबई के माटुंगा (ब्राह्मणवाड़ा) में भारी श्बारिश और तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने और जलभराव की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा, रियल एस्टेट क्षेत्र में इस इलाके में पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) की परियोजनाओं और संपत्ति के नए सौदों को लेकर काफी चर्चा है। मौसम और जलभराव (Weather & Waterlogging) मुंबई में रेड अलर्ट के बीच माटुंगा में भारी बारिश और 70-80 किमी/घंटे की रफ्तार से चली हवाओं से कई स्थानों पर पेड़ गिरे। माटुंगा स्टेशन पर भी जल जमाव के कारण आवागमन बाधित हुआ।

पब्लिक ऐप, भारत के लिए बनी भारत की सबसे भरोसेमंद शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म ने 80 मिलियन यूजर्स का टप्पा पार कर लिया

मुंबई। पब्लिक ऐप, भारत का सबसे भरोसेमंद शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, ने 80 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है जो 700+ जिलों और 12 भारतीय भाषाओं में हर महीने 15 बिलियन से ज्यादा व्यूज पहुंचा रहा है। यह वही प्लेटफॉर्म बन गया है जहां भारत रीयल-टाइम लोकल अपडेट्स, कम्युनिटी स्टोरीज और अपनी भाषा में कंटेंट के लिए आता है यह एक ऐसा इकोसिस्टम जो अब देश के सबसे छोटे शहरों तक यूजर्स तक पहुँच रहा है। पब्लिक ऐप, इनशॉर्ट्स ग्रुप का हिस्सा है, जो इनशॉर्ट्स के साथ मिलकर भारत के हर कोने में 92 मिलियन से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचता है। पब्लिक ऐप ने भारत के रोजगार के हितों के आसपास डिजाइन किया गया एक कंटेंट इकोसिस्टम बनाया है। यह स्थानीय अपडेट, सामुदायिक कार्यक्रमों, नागरिक और सार्वजनिक अलर्ट, भक्ति और सांस्कृतिक सामग्री, सीखने और कौशल-निर्माण श्रृंखला, और क्षेत्रीय मनोरंजन, सभी को एक साथ लाना, जो लोग वास्तव में बोलते हैं। स्थानीय घटनाओं का वास्तविक समय कवरेज और प्रामाणिक, समुदाय-संचालित कहानी कहने का मंच के केंद्र में बैठता है, जो एआई-संचालित स्टैक के माध्यम से वितरित किया जाता है जो बड़े पैमाने पर सामग्री को स्रोत, व्यवस्थित और वितरित करता है। दीपित पुरकायस्थ, को-फाउंडर और सीईओ, इनशॉर्ट्स ग्रुप ने कहा, पब्लिक ऐप ने एक आइडिया पर ध्यान केंद्रित करके 80 मिलियन यूजर्स का मुकाम पार किया है कि भारत को ऐसा वीडियो प्लेटफॉर्म चाहिए जो उसकी लाइफस्टाइल, सीखने के तरीके और जुड़ने के अंदाज के हिसाब से बनाया गया हो। स्क्रोल करने के टाइम के लिए ऑप्टिमाइज किए गए फीड के लिए नहीं, बल्कि ऐसा जगह जहां नासिक के किसान, जौनपुर के पहली पीढ़ी के छात्र, और बीकानेर के दुकानदार अपनी भाषा में और जिस पर उन्हें भरोसा हो ऐसे कंटेंट तक आसानी से पहुंच सकें।

इंदौर के मुसाखेड़ी ओवरब्रिज का काम देखने पहुंचे कलेक्टर, बोले- क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज

-प्रणित नरेंद्र तिवारी

इंदौर (उत्तरशक्ति)। इंदौर के मुसाखेड़ी में बन रहे ओवरब्रिज का काम जल्द रफ्तार पकड़ेगा। बुधवार को कलेक्टर शिवम वर्मा ने निमार्णाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को काम तेज करने और तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने कहा कि जब तक फ्लाइओवर का काम चलता है, तब तक लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सर्विस लेन की मरम्मत और पेचवर्क कराया जाए। उन्होंने बताया कि आईटी पार्क की सर्विस लेन को दो दिन में चालू करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ट्रैफिक वहां से डायवर्ट किया जा सके।कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जहां भी ट्रैफिक डायवर्ट किया जाए, वहां की सड़क पहले ठीक की जाए। खराब सड़क होने पर जाम और परेशानी बढ़ती है। उन्होंने साफ कहा कि डायवर्जन ऐसा हो, जिससे वाहन आसानी से निकल सकें। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अन्य विभागों से जुड़े लंबित काम और बाधाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी अड़चनें जल्द दूर की जाएं, ताकि निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ सके। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्माण कार्य की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि काम समय पर पूरा हो, लेकिन गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही यह ओवरब्रिज बनने के बाद इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को आने-जाने में राहत मिलेगी।

संस्था को बाल श्रम मुक्त बनाने की डीएम ने दी सहमति

केराकत,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत तहसील क्षेत्र की चर्चित संस्था आस्था महिला एवं बाल विकास के पदाधिकारी मंगलवार को जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह से शिष्टाचार भेंट कर पुष्प गुच्छ एवं बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का मोमेंटो देकर धन्यवाद ज्ञापित किया।इस दौरान संस्था के निदेशक संतोष कुमार पांडेय ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की पूर्ण जानकारी व वार्षिक गतिविधियों का रिपोर्ट साझा की गई। इस बाबत जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने संस्था द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए 2027 तक जनपद को बाल श्रम मुक्त बनाने की पूर्ण सहमती दी।इस अवसर पर बंदना कुमारी,दीपनारायण,खुशी चंद,सविता,एड.विनय कुमार तिवारी समेत आदि लोग मौजूद रहे।

ट्रेन की पैंट्री कार में स्वच्छता नियमों का सख्ती से पालन किया जाए : रेल मंत्रालय

नईदिल्ली। रेल मंत्रालय ने ट्रेन की पैंट्री कार में गंदगी की खबरों पर चिंता जताते हुए सभी जोन को साफ-सफाई से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने सभी जोन कार्यालयों को सात जुलाई को भेजे पत्र में कहा, मुख्य डिपो में पैंट्री कार की सफाई, कीटाणुनाशक और चूहों की रोकथाम के बारे में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के बावजूद अलग-अलग स्रोत से पैंट्री कार में गंदगी के साथ-साथ कीड़े-मकोड़ों और चूहों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं।श् पत्र में कहा गया है कि ऐसी घटनाओं से यात्रियों की सुविधा, साफ-सफाई और भारतीय रेलवे की छवि पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए इन पर तुरंत और लगातार ध्यान देने की जरूरत है। इसमें कहा गया है, श्शिकायतों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर दोहराया जाता है कि सभी जोनल रेलवे को पैंट्री कार की सफाई, रखरखाव, चूहों आदि की रोकथाम के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों का नियमित रूप से पालन करना चाहिए।

महाराष्ट्र में मॉनसून का तांडव: 62 लोगों की मौत, 200 पशुओं की गई जान

मुंबई। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। वहीं नदियों के उफान और इमारतों के ढहने जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की ओर से बुधवार को जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जून से अब तक राज्य में 62 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 पशुओं की भी जान गई है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (एसईओसी) के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य के कोस्टल और पश्चिमी जिलों में अत्यधिक बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा असर ठाणे और पालघर में देखने को मिला। इस दौरान ठाणे में 196.9 मिमी, पालघर में 185.4 मिमी, रायगढ़ में 134.1 मिमी, मुंबई उपनगर में 125.0 मिमी और पुणे में 69.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के अनुसार, 1 जून से अब तक हुई कुल बारिश के आधार पर लगभग सभी जिले 'लार्ज एक्सेस' (सामान्य से बहुत अधिक बारिश) की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। पालघर में सामान्य से 457.3 प्रतिशत और पुणे में 435.4 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, पिछले पांच सप्ताह में हुई 62 मौतों में सबसे अधिक जानें इमारतों और दीवारों के ढहने तथा आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में गई हैं। संरचनाओं के ढहने से 25 लोगों की मौत हुई और 41 लोग घायल हुए। ये घटनाएं मुख्य रूप से नासिक, ठाणे, और मुंबई उपनगर में हुईं। वहीं बिजली गिरने की घटनाओं में 23 लोगों की मौत और 17 लोग घायल हुए। राज्य में हुई 200 पशुओं की मौत में से 181 की मौत बिजली गिरने के कारण हुई। इसके अलावा भूस्खलन और मलबा खिसकने की घटनाओं में 6 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हुए। इन घटनाओं का सबसे ज्यादा असर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, सतारा और पुणे के पहाड़ी इलाकों में देखने को मिला। पेड़ गिरने की घटनाओं में 6 लोगों की जान गई, जबकि बाढ़ के कारण 2 लोगों की मौत हुई। हाल की घटनाओं में मुंबई उपनगर में दीवार गिरने से एक व्यक्ति घायल हुआ, जबकि रत्नागिरी में पेड़ गिरने से दो लोग घायल हो गए। लगातार बारिश के कारण राज्य की कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके चलते कई निचले इलाकों के गांवों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) ने महाराष्ट्र के पूरे समुद्री तट के लिए मध्यरात्रि तक रेड अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने लोगों को समुद्र तट के पास होने वाली सभी मनोरंजक गतिविधियां पूरी तरह बंद रखने की सलाह दी है।

मिलावटी मसालों के खिलाफ खाद्य विभाग का अभियान, 11 कुंतल से अधिक मसाला सीज

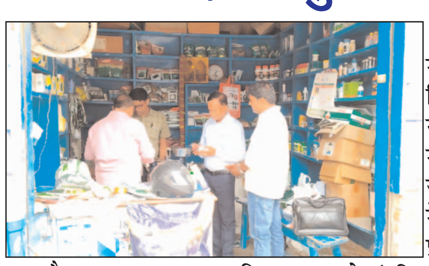

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जनपद में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। जिलाधिकारी के निर्देश एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुपालन में विभागीय टीम ने विभिन्न बाजारों में स्थित मसाला निर्माण इकाइयों और थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। सहायक आयुक्त (खाद्य-द्वितीय) डॉ. मंजुला सिंह के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार जायसवाल के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में कई प्रतिष्ठानों से मसालों के नमूने संग्रहित किए गए।

पचहटियां बाजार विशेषरपुर स्थित मां शीतला ट्रेडिंग कम्पनी से धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर के नमूने लेकर क्रमशः 360 किलोग्राम एवं 750 किलोग्राम मसाला सीज किया गया। वहीं मतापुर जगदीशपट्टी स्थित क्यारी एग्रो से खिचड़ी मसाला का नमूना लेकर 14 किलोग्राम मसाला जब्त किया गया। इसके अलावा धौरइल गांव शाहगंज स्थित प्रतिमा इंटरप्राइजेज, कलेक्टरगंज शाहगंज स्थित शाहगंज ट्रेडिंग कम्पनी, केवटली महराजगंज बाजार बदलापुर स्थित प्यारे लाल हनुमानदीन तथा सोईथा शीतलगंज बाजार स्थित थोक विक्रेता के प्रतिष्ठानों से विभिन्न ब्रांडों के मसालों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार अभियान के दौरान कुल 07 नमूने खाद्य विश्लेषक को प्रेषित किए गए तथा लगभग 11 कुंतल 24 किलोग्राम मसाला, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 73 हजार 480 रुपये है, को सीज किया गया। विभाग ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

बांग्लादेश में बड़ा हादसा: रोहिंग्या कैंप में भूस्खलन, आठ शरणार्थियों की मौत

नईदिल्ली। पूर्वी बांग्लादेश में भारी मानसूनी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम आठ रोहिंग्या शरणार्थियों की मौत हो गई, जिनमें पांच बच्चे शामिल हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कॉक्स बाजार जिले में दमकल सेवा और नागरिक सुरक्षा अधिकारी डॉलर त्रिपुरा ने बताया कि बचावकर्मियों ने सात शव बरामद किए, जबकि आठवां शव शरणार्थियों को मिला। उन्होंने बताया कि यह घटना सुबह तक कई पहाड़ियों के ढहने के कारण हुई। उन्होंने बताया कि दो अन्य बच्चे भी घायल मिले हैं। अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश और पहाड़ियों से बहते तेज पानी के कारण अस्थायी मकान ढह गए। त्रिपुरा ने बताया कि भूस्खलन से शिविरों में कम से कम चार स्थान प्रभावित हुए, जिससे ये असथायी घर मिट्टी और मलबे के नीचे दब गए। उस समय इनमें रहने वाले लोग सो रहे थे।

गुरदासपुर में मंदिर में बड़ी वारदात, आरोपी को भीड़ ने रंगे हाथों पकड़ा

गुरदासपुर (हरजिंदर गोराया)। गुरदासपुर के बबरी बाईपास स्थित मेरिटोरियस स्कूल के नजदीक बने शिव शक्ति मंदिर में दिनदहाड़े तोड़फोड़ और चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के अनुसार, मंदिर के महंत देवा जी मंदिर का मुख्य गेट बंद कर किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान एक युवक, जो देखने में प्रवासी प्रतीत हो रहा था, मंदिर की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गया। आरोप है कि युवक ने चोरी की नीयत से मंदिर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। उसने मंदिर में स्थापित मूर्तियों के आभूषण उतार लिए और पीतल व तांबे की मूर्तियों सहित अन्य कीमती सामान अपने बैग में भर लिया। घटना को अंजाम देने से पहले उसने मंदिर परिसर में लगे सभी उउळश कैमरों की तारें भी काट दीं, ताकि उसकी गतिविधियां रिकॉर्ड न हो सकें। हालांकि, इससे पहले कि आरोपी मंदिर से बाहर निकल पाता, बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और उसे घेर लिया। आरोप है कि युवक ने श्रद्धालुओं पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे काबू कर लिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद श्रद्धालुओं में भारी रोष है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

रिटायर्ड ARTO के घर कुबेर का खजाना: 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और करोड़ों की नकदी बरामद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सतर्कता अधिष्ठान ने आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में अधिक संपत्ति अर्जित करने के एक मामले में आगरा में तैनात रहे पूर्व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) ललित कुमार के लखनऊ स्थित घर पर छापेमारी करके भारी मात्रा में सोना-चांदी और नकदी बरामद की। सतर्कता अधिष्ठान की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के मुताबिक अदालत से तलाशी वारंट मिलने बाद मंगलवार और बुधवार को अलीगंज की चंद्रलोक कॉलोनी में स्थित कुमार के घर पर की गई छापेमारी के दौरान एक करोड़ 62 लाख रुपये नकदी, 13 किलोग्राम सोना और नौ किलोग्राम चांदी के गहने बरामद किये गए। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा चल–अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी मिले, जिनकी कुल कीमत लगभग 35 करोड़ रुपये आंकी गई है। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौर ान कथित तौर पर पता चला था कि कुमार ने आय के ज्ञात स्रोतों के अनुताप में कहीं अधिक संपत्ति जमा की है, जिसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान इस मामले की जांच कर रहा है। बयान के अनुसार छापेमारी के दौरान मिले एक करोड़ 62 लाख रुपये घर के अंदर अलग-अलग स्थानों पर पैकेट में छुपाकर रखे गए थे, वहीं लगभग 13 किलो सोना और लगभग नौ किलो चांदी भी जब्त की गयी है। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कई चल और अचल संपत्तियों में निवेश से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किये गये हैं। बयान के मुताबिक, ये दस्तावेज लखनऊ में कई रिहायशी मकानों और भूखंड, लखनऊ, बाराबंकी और रायबरेली जिलों में कृषि भूमि और लखनऊ व नोएडा में फ्लैट की बुकिंग से संबंधित हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 13 करोड़ रुपये है। बयान के अनुसार छापेमारी में बैंक में जमा राशि, डाकघर में निवेश, म्यूचुअल फंड और सावधि जमा में एक करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। अधिकारियों ने बताया कि मौके से दो कीमतें कारें और एक रिवॉल्वर भी बरामद की गई। उन्होंने बताया कि बरामद नकदी, कीमती धातुओं, गहनों, चल-अचल संपत्ति और निवेश की कुल कीमत लगभग 35 करोड़ रुपये आंकी गई है। बयान में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के महानिदेशक ने यह छापेमारी और बरामदगी करने वाली टीम को एक लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है।

काशी में पहली बार बनेंगे थीमैटिक पार्क, संविधान से लेकर जीआई और वार मेमोरियल तक दिखेगी शहर की सांस्कृतिक विरासत!

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद में धर्म और संस्कृति की राजधानी काशी अब अपने पार्कों के माध्यम से भी इतिहास, विरासत और राष्ट्रभावना की नई पहचान गढ़ने जा रही है। नगर निगम ने शहर के विभिन्न उद्यानों को अलग-अलग विषयों पर विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत पहली बार वाराणसी में 'थीमैटिक पार्क' विकसित किए जाएंगे, जहां हर पार्क किसी विशेष विषय पर आधारित होगा। इन पार्कों का उद्देश्य केवल हरियाली और मनोरंजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि नागरिकों, बच्चों और पर्यटकों को शिक्षा, संस्कृति, इतिहास और स्थानीय विरासत से जोड़ना भी है।

मलदहिया नील कॉटेज पार्क बनेगा संविधान पार्क, बादशाह बाग वार मेमोरियल पार्क

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव के अनुसार, पहले चरण में दो पार्कों का विकास किया जा रहा है। मलदहिया स्थित नील कॉटेज पार्क को संविधान पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां भारतीय संविधान की मूल भावना, संविधान निमार्ताओं के योगदान, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों को आधुनिक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं बादशाह बाग पार्क को वार मेमोरियल पार्क का स्वरूप दिया जाएगा, जिसमें देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की गाथाएं, सैन्य इतिहास और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी।

नौ पार्कों का अलग-अलग थीम पर होगा विकास

योजना के तहत शहर के कुल नौ पार्कों को अलग-अलग थीम पर विकसित किया जाएगा। दुगाकुंड पार्क को कबीर दास पार्क बनाया जाएगा, जहां संत कबीर के जीवन, उनके दोहों, दर्शन और सामाजिक संदेशों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा कैंटोनमेंट क्षेत्र में जीआई पार्क विकसित होगा, जिसमें बनारसी साड़ी, गुलाबी मीनाकारी, लकड़ी के खिलौने, धातु शिल्प सहित वाराणसी के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। वेस्ट टू वंडर पार्क, ताल पार्क और संगीत एवं सांस्कृतिक विरासत पर आधारित अन्य थीम पार्क भी इस परियोजना का हिस्सा होंगे।

पार्कों में लाइटिंग, डिजिटल डिस्प्ले की रहेगी व्यवस्था

इन पार्कों में आधुनिक लाइटिंग, आकर्षक मूर्तियां, डिजिटल डिस्प्ले, सूचना पट्ट, बच्चों के लिए मनोरंजन क्षेत्र और बैठने की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम का मानना है कि इन पार्कों के विकसित होने से पर्यटकों को मंदिरों और घाटों के साथ-साथ काशी की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और शिल्प विरासत को समझने का नया अवसर मिलेगा। वहीं स्थानीय बच्चों और युवाओं को भी संविधान, स्वतंत्रता संग्राम, संत परंपरा और स्थानीय इतिहास की जानकारी रोचक तरीके से प्राप्त होगी।

110 मालियों की होगी नियुक्ति

नगर निगम ने परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और निर्माण कार्य चरणबद्ध ढंग से कराया जाएगा। पार्कों के रखरखाव के लिए 110 मालियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही नगर निगम अपनी नर्सरी भी विकसित कर रहा है, जहां तैयार किए जाने वाले पौधों से पार्कों की हरियाली और शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा।